वर्ष-चार, अंक-06 सितंबर-2024, मूल्यः 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

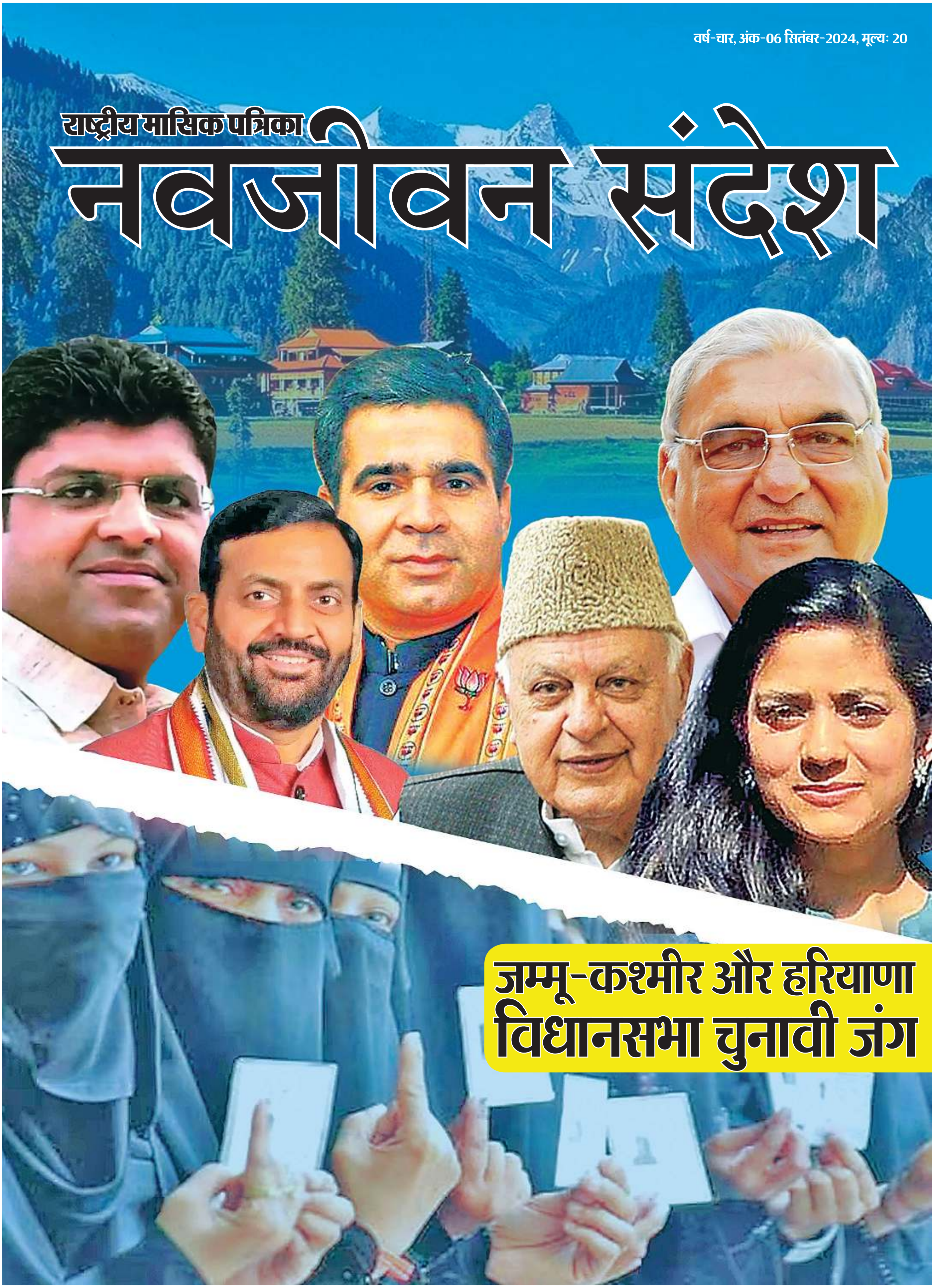

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावी जंग

RNI No : JHAHIN/2021/83133

नाल्को के नए सीएमडी होंगे बीपी सिंह

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने बृजेन्द्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), एक अनुसूची 'ए' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद के लिए चुना है।

कुल छह लोगों का साक्षात्कार लिया गया। वर्तमान में, सिंह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में प्रभारी निदेशक (बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट) के पद पर तैनात हैं। अपेक्षित मंजूरी और एसीसी की मंजूरी के अधीन, वह श्रीधर पात्रा की जगह लेंगे, जो 31.10.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह पद 1 नवंबर, 2024 को रिक्त होगा क्योंकि मौजूदा सीएमडी श्रीधर पात्रा 31 अक्टूबर, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने सिंह के नाम की सिफारिश की है, जो अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के प्रभारी निदेशक (बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट) होंगे।

इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद (आईएसएम) के पूर्व छात्र श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) और आईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर के प्रभारी निदेशक का कार्यभार बखूबी संभाला है। वह डीएसपी में कार्यकारी निदेशक (कार्य) के पद पर भी योगदान कर चुके हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यकारी निदेशक (संचालन) के रूप में

2019 में, उन्हें कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और भिलाई स्टील प्लांट में कार्यकारी निदेशक (संचालन) के रूप में नियुक्त किया गया। उसी वर्ष दिसंबर के अंत में उन्हें भिलाई स्टील प्लांट में कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) के रूप में फिर से नामित किया गया था। महामारी में उन्होंने प्लांट में परिचालन का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। प्रतिबंधित शर्तों के बावजूद संयंत्र का उत्पादन बरकरार रखा गया। उन्होंने 3 सितंबर, 2020 को डीएसपी में ईडी (वर्क्स) के रूप में पदभार संभाला और रिकॉर्ड समय में सभी तीन कनवर्टर्स के कनवर्टर शेल बदलने के कार्य को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। उनके कुशल मार्गदर्शन में एमएसएम ने उत्पादन में तेजी लायी।

शैक्षिक पृष्ठभूमि

बी पी सिंह ने आईएसएम धनबाद (अब आईआईटी आईएसएम) से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की और 1990 में सेल में शामिल हो गए। उन्होंने सेल की एक इकाई भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) की लौह अयस्क खदान में अपना करियर शुरू किया। बाद में वह अपना सराहनीय प्रदर्शन दिखाकर बीएसपी में खान प्रमुख बने और बीएसएल, बोकारो में विभिन्न परिचालन क्षेत्रों से भी जुड़े रहे।

index

RNI No: JHAHIN/2021/83133

नवजीवन संदेश
राष्ट्रीय मासिक पत्रिका
Web : navjeewansandesh.com
संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)
▪ वर्ष -4, ▪ अंक -06, ▪ कुल पृष्ठ -36

प्रधान संपादक
पंकज कुमार सिंह
संपादक
प्रभात मजुमदार
संपादक मंडल
जगन्नाथ मुंडा
सुनीता सिन्हा
श्रीमती छाया
रविप्रकाश
खेल डेस्क प्रभारी
चंचल भट्टाचार्य
छायाकार
नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799
9835437102
ईमेल: navjeewansandesh@gmail.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले झारखंड के तीन दुश्मन.... पेज-09

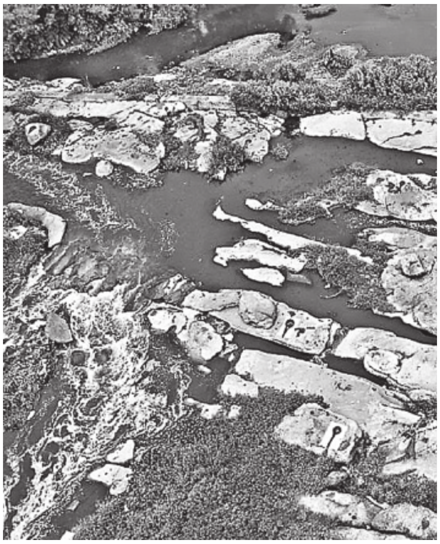

इक्कीसो महादेव का स्थापत्य दर्शन पेज-25

पेरिस पैरालंपिक में अपने सबसे सफल प्रदर्शन से भारत... पेज-31

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी.,बी. कॉर्प लि. प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित।
संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)
आरएनआई नं.: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

बेतहाशा बढ़ रही हैं सांप के काटने से मौतें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि सांप के काटने से होने वाली मौतें एक बड़ी समस्या बन रही हैं क्योंकि दवाओं की कमी हो रही है. जलवायु परिवर्तन के कारण भी सांप के काटने की समस्या बढ़ रही है.विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि हर साल हजारों लोगों की जान लेने वाली सांप के काटने की समस्या जलवायु परिवर्तन से होने वाली बाढ़ के कारण और गंभीर हो रही है. डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यह समस्या खासकर उन देशों में ज्यादा घातक बन रही है जहां एंटी वेनम (सांप के जहर का इलाज) की पहुंच बहुत कम है.

दुनियाभर में हर साल लगभग 27 लाख लोग जहरीले सांपों द्वारा काटे जाते हैं, जिनमें से करीब 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है. डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ डेविड विलियम्स ने जेनेवा में पत्रकारों से कहा, "हर चार से छह मिनट में एक व्यक्ति सांप के काटने से मरता है."

सांप के काटने की समस्या के विशेषज्ञ विलियम्स ने कहा कि सांप के जहर से जितने लोग मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा विकलांग हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि हर साल सांप के जहर से लगभग ढाई लाख लोग स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं.

सांप के जहर से शरीर में लकवा मार सकता है जिससे सांस रुक सकती है, खून संबंधी विकार हो सकते हैं और घातक रक्तस्राव का कारण बन सकते हैं क्योंकि सांप का जहर खून का थक्का बनने से रोकता है. इसके अलावा किडनी फेल हो सकती है और ऊतकों की क्षति हो सकती है, जो स्थायी विकलांगता और अंगों के नुकसान का कारण बन सकता है.

सांप के काटने के ज्यादातर शिकार लोग दुनिया के उष्णकटिबंधीय और गरीब क्षेत्रों में रहते हैं, और बच्चों पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि उनके शरीर का आकार छोटा होता है.

विलियम्स ने कहा कि सांप के काटने से होने वाली विकलांगताएं न केवल पीड़ितों को, बल्कि उनके पूरे परिवार को गरीबी में धकेल सकती हैं. इसका इलाज बहुत महंगा होता है और अगर पीड़ित व्यक्ति परिवार का कमाऊ सदस्य हो तो आय का नुकसान गंभीर गरीबी का कारण बन सकता है.

विलियम्स ने यह भी चेतावनी दी कि एक बड़ी समस्या यह है कि "दुनिया के कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षित और प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है." सब-सहारा अफ्रीका का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां अनुमानित जरूरत के केवल 2.5 प्रतिशत इलाज ही उपलब्ध हैं.

संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने 2019 में इस बात पर चिंता जताई थी कि 1980 के दशक से कई कंपनियों ने जीवनरक्षक जहर रोधी दवाओं का उत्पादन बंद कर दिया, जिससे अफ्रीका और कुछ एशियाई देशों में इसकी गंभीर कमी हो गई है.

विलियम्स ने बताया कि भारत सांप के काटने से सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां हर साल लगभग 58,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं, जबकि उसके पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान भी बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में है.

विलियम्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कुछ स्थानों पर स्थिति और खराब हो रही है. उन्होंने कहा कि खासकर बाढ़ के कारण सांप के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं. न्होंने नाइजीरिया का उदाहरण दिया, जो इस वक्त "सांप के जहर के इलाज की गंभीर कमी से जूझ रहा है, क्योंकि बाढ़ के कारण सांप के काटने के अतिरिक्त मामले सामने आ रहे हैं." विलियम्स ने कहा, "और यह समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां इस तरह की आपदाएं नियमित रूप से आती हैं." पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण सूडान और अन्य देशों में भी बड़ी बाढ़ के बाद सांप के काटने के मामलों में वृद्धि देखी गई है.

2008 में ग्लोबल स्नेक बाइट इनिशिएटिव की स्थापना करने वाले विलियम्स ने यह भी चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण विषैले सांपों की संख्या और उनके फैलने के क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, जिससे उन देशों में भी खतरा बढ़ सकता है, जो अब तक इससे अप्रभावित रहे हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून 2017 में सांप के काटने से होने वाले जहर को अपनी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) की प्राथमिकता सूची में जोड़ा था. एक राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन (मिलियन डेथ स्टडी) ने भारत में हर साल सांप के काटने से होने वाली 45,900 मौतों को दर्ज किया. इस अध्ययन के मुताबिक भारत में, सांप के काटने के लगभग 90 फीसदी मामले चार प्रमुख सांपों, करैत, भारतीय कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल वाइपर के कारण होते हैं.

मेलबर्न यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस अध्ययन में बताया गया कि भारत में सांप का जहर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की आबादी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. इस अध्ययन के मुताबिक भारत में हर साल सांप काटने के 14 से 28 लाख ऐसे मामले दर्ज होते हैं जो घातक नहीं होते.

भारत के 6,671 क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर आधारित ये आंकड़े बताते हैं कि सांप काटने से 82-97 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, और 77 फीसदी जानें वहां जाती हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है. मानसून के दौरान सूखे मौसम की तुलना में कहीं अधिक मौतें होती हैं. अध्ययन में पाया गया कि मानसून में मौतों की मासिक दर 5,000-7,000 थी जबकि सूखे मौसम में 2,000 जानें प्रति माह गईं. इस तरह भारत में सांप काटने से औसत मृत्यु दर 3.0-4.5 प्रति 1,00,000 व्यक्ति प्रति वर्ष है.

तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण समुदायों में किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि यह संख्या तीन गुना अधिक हो सकती है क्योंकि केवल उसी क्षेत्र में 10,000 मौतें हर साल हो रही हैं. इसी तरह, पश्चिम बंगाल में सांप के काटने की घटनाओं पर किए गए एक सामुदायिक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 7.2 फीसदी मौतें आधिकारिक रूप से दर्ज की गई थीं. उस अध्ययन में यह भी पाया गया कि केवल 22.9 फीसदी मरीज अस्पताल पहुंचे थे, और क्षेत्र में सांप के काटने से होने वाली 65.7 फीसदी मौतें न्यूरोटॉक्सिक करैत के काटने से हुई थीं.

अध्ययन में पाया गया कि सांप के काटने के 24 घंटे से अधिक देर से पहुंचने वाले मरीजों में मृत्यु दर 18 फीसदी थी, जबकि 24 घंटे के भीतर पहुंचे मरीजों में यह दर 5 प्रतिशत थी.

हरियाणाः चुनावी मुद्दों से मिल रहे हैं सत्ता-विरोधी संकेत

▪ ललित गर्ग

» अरविंद केजरीवाल के जातीय गणित के कारण 'आप' पार्टी कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है तो कुछ नुकसान भाजपा का भी कर सकती है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों में उठापटक हो रही है, दलबदल का सिलसिला जारी है, गठबंधन टूट रहे हैं जो नये जुड़ रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर भाजपा के सामने इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं, वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से अति-उत्साहित दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने में जुटी है। हरियाणा में तू डाल-डाल, मैं पात-पात की कशमकश जोरों से चल रही है। विनेश और बजरंग पहलवान को शामिल करके कांग्रेस खुशियां मना रही थी, लेकिन 'आप' से हो रहा समझौता टूटते ही कांग्रेस की खुशियां कुछ हद तक फीकी दिखाई देने लगीं। फिर भी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में अपनी बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा भी यहां अपनी सरकार बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार हरियाणा के चुनावों पर समूचे देश की नजरे लगी है।

हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद से कांग्रेस के जीत के सपनों को सेंध लगी है। आप ने प्रत्याशियों की दो-दो सूची जारी कर दी है, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान भी कर दिया है। फिर भी दोनों दलों में कुछ लोग हैं, जो अभी गठबंधन की उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि यही गठबंधन कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण माना जा रहा है। इस गठबंधन के टूटन से भाजपा की निराशा के बादल कुछ सीमा तक छंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाजपा की जीत अभी भी निश्चित नहीं मानी जा रही है। भले ही 'आप' को दूर रखकर हरियाणा कांग्रेस की राज्य इकाई खुश हो रही हो, लेकिन इसका फायदा भाजपा को ही होने वाला है क्योंकि 'आप' प्रत्याशियों को जहां भी, जितने भी वोट मिलने वाले हैं, वे जाएंगे कांग्रेस के खाते से ही। इस त्रिकोणीय संघर्ष का फायदा भाजपा को ही मिलेगा।

हरियाणा कांग्रेस एवं उसके नेता प्रारंभ से ही स्वतंत्र चुनाव लड़ने के पक्ष में रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, दस वर्षों की सत्ता-विरोधी लहर के मद्देनजर भाजपा 2019 से कमजोर स्थिति में है, जब उसे 90 सीटों की विधानसभा में 40 सीटें ही मिल पाई थीं। हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों के नतीजे भी संकेत दे रहे हैं जहां पिछली बार की दसों सीटों की जगह उसे सिर्फ 5 सीटें मिलीं। आप को कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वह हार गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए ही प्रदेश कांग्रेस आप के साथ गठबंधन को पूरी तरह गैर जरूरी मान रहा है। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राजनीति गणित को देखते हुए आप के साथ गठबंधन को लेकर निरन्तर प्रयास करता रहा। यही कारण दोनों दल गठबंधन के लिए बातचीत की मेज पर बैठे। राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनकी प्राथमिकता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की एकजुटता और उसकी मजबूती में किसी तरह की कमी न दिखे ताकि केंद्र सरकार और भाजपा पर उसका दबाव बना रहे।

हरियाणा में आप पार्टी कोई चमत्कार घटित करने की स्थिति में नहीं है। उसकी भूमिका सत्ता के गणित को प्रभावित करना मात्र है। कुछ सीटें उसके खाते में जा सकती है, जिसका रोल भविष्य की सत्ता की राजनीति में हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के जातीय गणित के कारण 'आप' पार्टी कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है तो कुछ नुकसान भाजपा का भी कर सकती है। कम वोटों के अंतर से होने वाली जीत-हार में 'आप' पार्टी का असर साफ दिखने वाला है। देर से ही सही, हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व को यह बात समझ में आ जाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी। हालांकि चुनाव परिणाम आने पर ही असल माजरा समझ आएगा, लेकिन यह तय है कि भाजपा को दस साल के राज के बावजूद कमजोर नहीं माना जा सकता।

लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में आई कमी के बाद विपक्ष को जो थोड़ी धार मिली है, उसका जो मनोबल बढ़ा था, उसके मद्देनजर ये चुनाव अहम माने जा रहे हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसे में

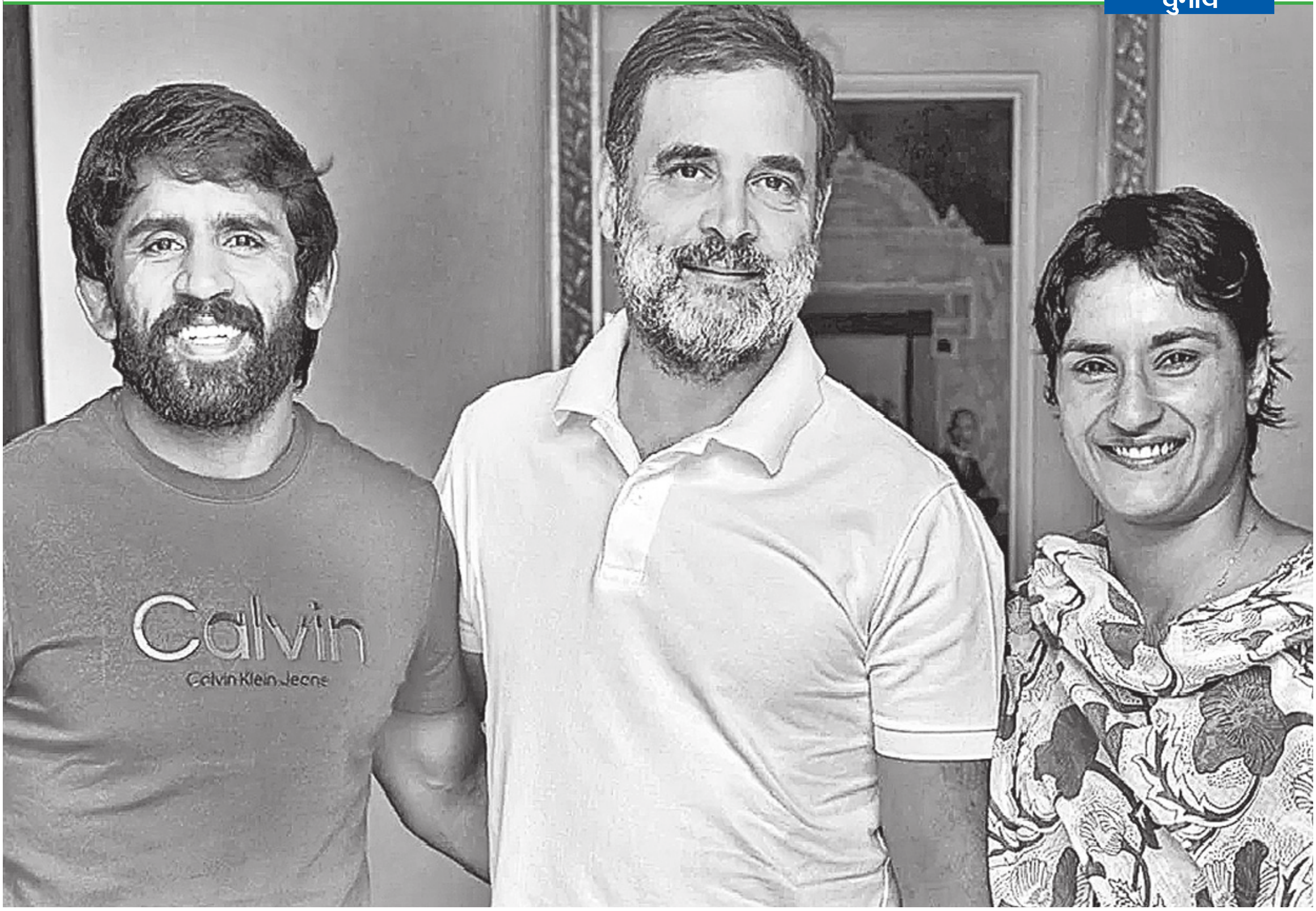

हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन साथ मिलकर मजबूती से लड़ता और अच्छी जीत दर्ज करा पाता तो उसका असर न केवल आने वाले विधानसभा चुनावों पर बल्कि पूरे विपक्ष के मनोबल पर पड़ने वाला था। इंडिया गठबंधन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही झेलना पड़ता है। इसलिये इस गठबंधन की मजबूती ही भाजपा के लिये असली चुनौती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को याद करें तो इस पर लगभग आम राय है कि वहां कांग्रेस को प्रदेश नेतृत्व के अति आत्मविश्वास का नुकसान हुआ। असल सवाल विपक्षी वोटों के बंटवारे का है। जिस तरह से आप प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, उससे साफ है कि वह इसी पहलू की ओर इशारा कर रही है कि उसे सीटें भले न आएं, कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान तो हो ही सकता है।

भाजपा लम्बे समय से हरियाणा में कमजोर बनी हुई है, भले ही सरकार उसी की हो। अपनी लगातार होती कमजोर स्थितियों में सुधार लाने एवं प्रदेश में भाजपा को मजबूती देने के लिये ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल के स्थान पर ओबीसी वर्ग के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता विरोधी कारकों को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा को उसका पूरा लाभ नहीं मिल सका। इसके मुख्य कारण सत्ता विरोधी वातावरण बना तो

- हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद से कांग्रेस के जीत के सपनों को सेंध लगी है। आप ने प्रत्याशियों की दो-दो सूची जारी कर दी है, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान भी कर दिया है।

किसानों व बेरोजगारों की नाराजगी बड़ी चुनौती बन कर सामने आयी। भाजपा द्वारा पेश किए गए तीन विवादास्पद कृषि कानून हरियाणा में विवाद का मुख्य मुद्दा बने हुए है। राज्य के किसानों ने इन कानूनों का विरोध किया, उनका दावा है कि ये उनकी फसल की बिक्री और आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। केन्द्र की अग्निपथ योजना भी इन चुनावों में एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। इसने राज्य के युवाओं में चिंता पैदा कर दी है।

आलोचकों का मानना है कि यह स्थायी भर्ती से दूर जाने का कदम है, जिससे सैनिकों के लिए रोजगार में अस्थिरता पैदा होती है। इन चुनावों में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, राज्य की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकारी नीतियों पर काफी बहस चल रही है, जिससे यह चुनावों में एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है।

पहलवानों से जुड़ा मामला और बृज भूषण शरण सिंह पर लगे आरोप भी हरियाणा चुनाव में अहम मुद्दा बन गए हैं। पहलवानों ने सिंह पर उन्हें न्याय और सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है, जिससे हरियाणा में राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जुड़ गया है। हरियाणा में पहलवानों की सबसे अधिक संख्या और कुश्ती में एक मजबूत परंपरा होने के बावजूद, समर्थन की कथित कमी पर चिंता है। खेलो इंडिया पहल में, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है, गुजरात को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया, जिससे हरियाणा के खेल समुदाय में असंतोष पैदा हुआ। यह मुद्दा राज्य में एथलीटों के लिए संसाधनों और समर्थन के वितरण में कथित असंतुलन को उजागर करता है। इन स्थितियों में विनेश और बजरंग पहलवान के कांग्रेस में शामिल होने का पार्टी को लाभ मिलेगा। हरियाणा चुनाव में उठाये जा रहे मुद्दों पर गौर करे तो ये संकेत भाजपा के लिये संकट का कारण बन रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार हरियाणा के चुनावों में लड़ाई कई दलों के लिये आरपार की है। 'अभी नही तो कभी नहीं'- हरियाणा का सिंहासन छूने के लिये सबके हाथों में खुजली आ रही है। इसमें हरियाणा के मतदाता की जागरूकता, संकल्प एवं विवेक ही प्रभावी भूमिका अदा करेंगा।

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर तक तीन चरण में मतदान

विस चुनाव से जम्मू-कश्मीर के लोगों में जगी नई उम्मीद

▪ रिफत फरीद

एक दशक बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है. यहां के निवासियों के लिए अपनी सरकार चुनने का यह मौका, कभी न खत्म होने वाली हिंसा के बीच उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. नई सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें हैं?

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो गयी है. तीन चरण में हो रहा मतदान 1 अक्टूबर को पूरा होगा. मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी. चुनाव के लिए महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है. दक्षिणी कश्मीर की एक चुनावी रैली में आईं दर्जनों महिलाएं अपने पसंदीदा उम्मीदवार के समर्थन में पारंपरिक गीत गाती नजर आईं.

करीब एक दशक में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव से इन महिलाओं के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी है. वे ऐसा प्रतिनिधि चाहती हैं, संभवतः ऐसी महिला प्रतिनिधि, जो उनकी रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं को हल कर सके. जैसे कि गांव में पानी की कमी, कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद स्थानीय लड़के और मुसलमान बहुल घाटी क्षेत्र में युवा बेरोजगारी की बढ़ती समस्या.

ये महिलाएं, बतौर उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती का समर्थन कर रही हैं. वह पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं. दक्षिणी कश्मीर की एक चुनावी रैली में आईं 45 साल की शमीमा जान ने इल्तिजा मुफ्ती के बारे में कहा, "वह युवा और ऊर्जावान हैं. अगर हम उन्हें वोट देते हैं, तो वह हमारी बात सुनेंगी. हमारे बहुत से युवा कश्मीर से बाहर के जेलों में बंद हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए."

शमीमा जान जिस समय यह बात कह रही थीं, उसी समय इल्तिजा मुफ्ती अपनी एसयूवी गाड़ी की छत से बाहर निकलकर भीड़ को संबोधित कर रही थीं. शमीमा ने आगे कहा, "इस चुनाव से हमारे हालात बदल सकते हैं." शमीमा के आसपास खड़ी महिलाओं ने भी सिर हिलाकर इस बात पर सहमति जताई.

जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव

2014 में हुआ था. उस समय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और क्षेत्रीय पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (पीडीपी) ने गठबंधन सरकार बनाई थी. 2018 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और गठबंधन सरकार टूट गई. इसके बाद केंद्र सरकार ने अलगाववादी हिंसा से जूझ रहे इस क्षेत्र को सीधे नियंत्रण में ले लिया था.

अब वर्षों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद एक बार फिर कश्मीर के लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिला है. जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित होने के बाद यह यहां का पहला विधानसभा चुनाव है.

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ-साथ बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, सभी इस चुनाव में भाग ले रही हैं. कई अलगाववादी भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े हैं. इससे पहले वे चुनावों का बहिष्कार करते थे. इस बार के चुनाव में उनके रुख में साफ तौर पर बदलाव नजर आ रहा है.

इस साल हुए लोकसभा चुनाव 2024 ने पहले ही नेताओं की एक नई पीढ़ी का संकेत दिया था, जिसमें अब्दुल रशीद शेख भी शामिल हैं. इनके समर्थक इन्हें 'इंजीनियर रशीद' के नाम से जानते हैं. सिविल इंजीनियर रहे रशीद शेख आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के आरोप में जेल में थे. उन्होंने जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी. संभावना जताई जा रही है कि उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) विधानसभा चुनाव में पुराने राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दे सकती है.

रशीद को इसी महीने अंतरिम जमानत दी गई है और उन्हें चुनावी अभियान में शामिल होने की अनुमति मिली है. कश्मीर के त्राल शहर में एआईपी की एक रैली में आए मंजूर अहमद ने डीडब्ल्यू को बताया, "हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि हम हमेशा डर के साये में नहीं रहना चाहते हैं. हम रशीद की बातों को सुनने के लिए काफी संख्या में यहां आए हैं क्योंकि उनके भाषण हमारे विचारों और सोच से मेल खाते हैं."

रशीद की एक और समर्थक अतीका जान ने बताया कि उनका बेटा जेल में है और वह उसे बाहर निकालना चाहती हैं. अतीका ने बताया, "मेरा बेटा पिछले एक साल से जेल में है. मैं यह बात रशीद को बताना चाहती थी क्योंकि वह मेरा दर्द समझ सकते हैं."

रशीद की पार्टी एआईपी ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी गुट के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन किया है. इस गुट के उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी, मुसलमान-बहुल कश्मीर घाटी में समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष करती रही है. हालांकि, हिंदू-बहुल जम्मू में पार्टी के पास अच्छा जनाधार है. इसके अलावा जम्मू बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है, जहां वह अपनी राष्ट्रवादी बयानबाजी, सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और विकास परियोजनाओं के वादों का लाभ उठा सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को जम्मू के डोडा जिले में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरे क्षेत्र को समृद्ध बनाया है. उन्होंने कहा, "हम और आप मिलकर कश्मीर को देश का एक सुरक्षित और समृद्ध हिस्सा बनाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि अलगाववादी हिंसा के बावजूद आतंकवाद "जम्मू-कश्मीर में अपनी अंतिम सांसे ले रहा है."

हालांकि, स्थानीय नेता बीजेपी के इन बदलाव के दावों को 'झूठा' बताते हुए खारिज करते हैं. कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, "बीजेपी कहती आ रही है कि हालात सुधर गए हैं, लेकिन यह उसके लिए शर्म की बात है कि वह पिछले 10 साल में जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाई. लोग परेशान हैं, उनका दम घुट रहा है."

2019 में राजनीतिक बदलावों के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के कारण नई निर्वाचित सरकार के पास सीमित शक्तियां होंगी. कानून-व्यवस्था और जमीन से जुड़े मुद्दे जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे और स्थानीय सरकार इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है.

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नूर मुहम्मद बाबा ने बातचीत करते हुए कहा, "यह चुनाव एक ही साथ काफी महत्वपूर्ण और महत्वहीन, दोनों है. महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह (चुनाव) लंबे समय बाद हो रहा है और लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिल रहा है. इससे यह संदेश भी जाएगा कि लोग किस तरह गुस्से में हैं और बदलावों पर अफसोस कर रहे हैं."

हालांकि, वह आगाह करते हैं कि उन्हीं बदलावों का मतलब है सरकार के पास 'कम शक्ति' होगी. नूर मुहम्मद बाबा कहते हैं, "अब लोग तय करेंगे कि वे बदलावों के पक्ष में हैं या उनके खिलाफ."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले झारखंड के तीन दुश्मनः जेएमएम, कांग्रेस-आरजेडी

विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे परआए। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के तीन दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी।

राजद तो अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है। वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो भाजपा को मौका दीजिए।

वहीं घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री ने जेएमएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। तुष्टिकरण की राजनीति में ये लोग सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम ने एक ही काम किया भ्रष्टाचार। जल-जंगल-जमीन सब लूटा है। उनके सांसद के घर से नोटों के पहाड़ मिलते हैं। टीवी में महीनों तक नोटों के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नकली नोट नहीं थे, ये आपकी मेहनत की कमाई थी।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन 7 बड़ी रेल योजना की शुरुआत भी की। वहीं जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए गए।

पहले ये सभी कार्यक्रमों की शुरुआत मोदी खुद टाटानगर रेलवे स्टेशन से करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। जिसके बाद वह सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। भारी बारिश के कारण बिष्टुपुर मेन रोड से गोपाल मैदान तक होने वाला उनका रोड शो भी रद्द कर दिया गया।

मोदी ने कहा कि यहां पेपर लीक करने वालों को शह दी जा रही है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार को हमें हटाना ही होगा। गरीबों को झांसा देने के लिए पेट्रोल-डीजल देने की योजना चलाई, लेकिन उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब महिलाओं को पैसा देने के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले बरगला रहे हैं। वादे करना और उसे पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम ने एक ही काम किया भ्रष्टाचार। जल-जंगल-जमीन सब लूटा है। उनके सांसद के घर से नोटों के पहाड़ मिलते हैं। टीवी में महीनों तक नोटों के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नकली नोट नहीं थे, ये आपकी मेहनत की कमाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने चंपाई सोरेन को लेकर क्या कहा?

झारखंड में चुनावों की तारीखें जैसे-जैसे पास आ रही हैं, प्रदेश में राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने जमशेदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया जहां उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का नाम लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा.

प्रधानमंत्री ने कहा, "क्या चंपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे? वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया. मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्ज़ाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी के दिल को गहरी चोट पहुंची है."

उन्होंने कहा, "सीता सोरेन जी को एक महिला होने के बावजूद अपमानित और बेदखल किया गया. इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता हर बहन हर बेटी देगी."

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था. चंपाई सोरेन ने बाद में पार्टी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि पार्टी में उनका अपमान किया गया है.

थी। आपका पैसा था। ये भ्रष्टाचार करने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वालों की पाई-पाई का हिसाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे आपका साथ चाहिए।

पीएम ने कहा कि झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन ये सारे सपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप जानते हैं इस देश की सबसे बईमान पार्टी और परिवार एक ही है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती हैं। जेएमएम वाले भी वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। ये सभी कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से आए हैं।

जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के तीन दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। इन्हें आप जितनी जल्दी पहचानेंगे, उतनी जल्दी झारखंड का विकास होगा।

पीएम ने कहा राजद तो अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है। वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

---करमा पर झारखंड की बहनों को पक्के मकान का तोहफा

मौके पर पीएम ने कहा कि कल ही कर्मा पर्व था। जहां बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है। इस मौके पर झारखंड की बहनों को आपके इस भाई की तरफ से पक्के मकान का तोहफा मिला है। आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं-बहनों के नाम पर हैं।

उन्होंने कहा बीते लोकसभा चुनाव में सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन था। पूरी जमात, बड़े-बड़े षड़यंत्र, बड़ी-बड़ी साजिशें, झूठ की इतनी बड़ी मशीनरी, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें... लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा।

सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं, इसलिए सड़क मार्ग से ही आप सबके दर्शन करने पहुंच गया।

झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर, 2024 में हो सकता है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होने वाला है। पिछला चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन में लड़ा था और जीत हासिल की थी। जेएमएम ने सबसे ज्यादा 30 सीट जीती थी तो कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

महाराष्ट्रः महायुति बचाने के लिए भाजपा सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने को तैयार

महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बचाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संकटमोचक की भूमिका में पहुंचे और कई बैठकें कीं। उन्होंने सहयोगी दलों को मनोवांछित सीटें देने की भी पेशकश की। उन्होंने सहयोगी दलों और भाजपा के नेताओं से कहा कि वे आपसी विवाद पर सार्वजनिक बयानबाजी बंद करें। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की समस्याओं से जूझने के बीच, अमित शाह ने सोमवार को गठबंधन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और इसके बाद दिल्ली रवाना होने से पहले मुंबई हवाईअड्डे पर सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के साथ बातचीत की।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमित शाह ने पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों को संदेश दिया कि वे कमर कस लें और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतने की दिशा में काम करें। उन्होंने साझेदार एकनाथ शिंदे और अजित पवार सीटों की अच्छी हिस्सेदारी का आश्वासन दिया है।

हवाईअड्डे पर हुई बैठक में जनता के बीच महायुति के बढ़ते मतभेद का सार्वजनिक होना मुख्य मुद्दा था। बैठक में शाह, सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी अध्यक्ष पवार के अलावा, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। भाजपा के चुनाव प्रबंधकों ने कहा कि पार्टी महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 125 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। शुरुआती आकलन यह है कि पार्टी 50 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब है कि बाकी 75 सीटों पर उसे अपनी कोशिशें दोगुनी करनी होंगी।

दोनों साझेदारों के बारे में भाजपा नेताओं ने कहा कि जहां शिवसेना को 75 से 80 सीटें मिलने की संभावना है, वहीं एनसीपी को 55-60 सीटें मिलेंगी। यह कमोबेश उस मांग से मेल खा रही है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी ने इसी के आसपास सीटें मांगी थीं।

सूत्रों ने कहा कि अमित शाह ने सभी नेताओं से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते हुए अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने और सार्वजनिक मंचों पर मतभेदों को उजागर करने से बचने का आग्रह किया।एनसीपी के प्रदेश प्रमुख सुनील तटकरे ने इसे "बहुत अच्छी बैठक" बताते हुए, कहाः "हमें भरोसा दिया गया कि सभी महायुति घटकों को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलेंगी, और हर मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाएगा।"अमित शाह रविवार शाम को मुंबई पहुंचे थे। अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान उन्होंने गणेश चतुर्थी उत्सव में भी हिस्सा लिया और परेल में लालबागचा राजा के अलावा अन्य स्थानों पर भी दर्शन किए। जबकि फडणवीस और शिंदे पूरे समय शाह के साथ मौजूद थे, पवार केवल हवाई अड्डे पर उनके साथ शामिल हुए। एनसीपी नेताओं ने कहा कि वह गणेश चतुर्थी के साथ बारामती में व्यस्त थे। शाह ने इस दौरान भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। इसमें भाजपा के चुनिन्दा क्षेत्रीय नेता बुलाये गये थे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से महायुति में उठापटक चल रही है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से केवल नौ पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 15 में से सात सीटों पर जीत हासिल की थी और एनसीपी ने तीन में से एक सीट पर जीत हासिल की थी। प्रतिद्वंद्वी महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने 30 सीटें जीतीं। 2019 के विधानसभा चुनाव की स्थिति भिन्न थी। उस समय भाजपा अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में थी, उसने कुल 164 सीटों में से 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। शिंदे जिस शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके पास 40 मौजूदा विधायक हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास 42 मौजूदा विधायक हैं। 2019 में अविभाजित शिवसेना ने 56 सीटें और अविभाजित एनसीपी ने 54 सीटें जीती थीं।

आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री

आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी. सीएम चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा, ''जब तक मैं सीएम हूं, मेरा एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना है. साथ ही मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करुंगी. मैं अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करुंगी.''

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर आतिशी ने कहा, "मुझे इस बात का दुख भी है कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं. मैं आज दिल्ली की दो करोड़ जनता की तरफ से यही कहना चाहती हूं कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है."

इससे पहले गोपाल राय ने कहा कि आतिशी मुश्किल हालात में दिल्ली की सीएम बन रही हैं.

गोपाल राय ने आरोप लगाया, ''बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने और सरकार को गिराने की कोशिश की. लेकिन हमने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया.''

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में सहमति बनी. विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा.

जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वह दो दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तभी से इस पद की दौड़ में आतिशी का नाम भी शामिल था.

हालांकि, उनके अलावा गोपाल राय और कैलाश गहलोत के साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नामों पर भी चर्चा थी. लेकिन अब 43 साल की आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है. विधानसभा चुनावों तक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी.

आतिशी के हक में गईं ये बातें?

दरअसल, बैठक के बाद आतिशी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था. केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी के पास सर्वाधिक मंत्रालय और विभाग रहे हैं. उन्होंने मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते, शिक्षा क्षेत्र में भी कई अहम काम किए थे और मनीष सिसोदिया की ग़ैर मौजूदगी में शिक्षा विभाग भी संभाला. माना जाता है कि आतिशी केजरीवाल की विश्वासपात्र हैं. पार्टी से जुड़े कई सूत्रों ने भी बातचीत में ये संकेत दिए थे कि मौजूदा परिस्थिति में वो ही सबसे आगे हैं.

2020 विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में आतिशी समेत किसी भी महिला को जगह नहीं मिली थी. तब आतिशी को कैबिनेट में जगह ना दिए जाने को लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इस कदम की आलोचना की थी. ये वह चुनाव था जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी. इनमें से आठ महिला विधायक थीं. लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में एक भी

महिला नेता को जगह नहीं दी थी. लेकिन वक्त के साथ-साथ दिल्ली के राजनीतिक हालात भी बदले.

मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी सरकार से लेकर पार्टी तक के मसले पर मोर्चा संभालते दिखीं. आतिशी साल 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनीं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आतिशी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की बेटी हैं.

आतिशी ने दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल से पढ़ाई की थी. आतिशी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की है. आतिशी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की. बाद में आतिशी को चिवनिंग स्कॉलरशिप भी मिली. बाद में आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया. वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कामों में सक्रिय रहीं.

बाद में आतिशी भोपाल आ गईं. यहां वो कई एनजीओ के साथ काम करने लगीं. इसी दौरान वो आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण के संपर्क में आईं. अन्ना आंदोलन के समय से ही आतिशी संगठन में सक्रिय रही हैं और अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार हैं.

आतिशी साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ीं. वह साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर काम कर रही थीं.

आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार- मनीष सिसोदिया की सलाहकार रहते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, स्कूल मैनेजमेंट कमिटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई.

आतिशी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की भी सदस्य हैं. आतिशी के पास फिलहाल दिल्ली सरकार में जो विभाग हैं उनमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन (टीटीई), पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी), ऊर्जा, राजस्व, योजना, वित्त, विजिलेंस, जल, पब्लिक रिलेशंस और कानून-न्याय जैसे डिपार्टमेंट शामिल हैं. वह दिल्ली के कालकाजी इलाक़े से विधायक हैं. आतिशी को पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 'आप' ने उनको पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था. उस वक्त वह आतिशी मार्लेना के तौर पर जानी जाती थीं. इससे पहले आतिशी आम तौर पर पर्दे के पीछे सक्रिय नेताओं में गिनी जाती थीं.

2019 में आम चुनावों के दौरान अचानक आम लोगों की भीड़ के सामने आतिशी के हाथ में माइक देखकर इसका अंदाज़ा होने लगा था कि वो चुनावी राजनीति में 'आप' की एक अहम महिला चेहरा बन सकती हैं. उसी चुनाव में प्रचार के दौरान आतिशी ने पार्टी के सभी रिकॉर्ड और चुनाव अभियान से जुड़े सभी कागजातों से अपना उपनाम यानी 'मार्लेना' हटा दिया था. उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के सरनेम की वजह से उन्हें विदेशी और ईसाई बताकर घेरना शुरू कर दिया था. हालांकि, आतिशी ने कहा था कि वह अपना सरनेम इसलिए हटा रही हैं क्योंकि वह अपनी पहचान साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहतीं. दरअसल, आतिशी के माता-पिता को वामपंथी झुकाव वाला माना जाता है और कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर आतिशी को 'मार्लेना' सरनेम दिया गया था. आतिशी के सरनेम पर छिड़े विवाद के बीच उस समय मनीष सिसोदिया उनके बचाव में उतरे और उन्हें 'राजपूतानी' बताया था.

सिसोदिया ने एक ट्वीट में लिखा था, 'मुझे दुख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी के धर्म को लेकर झूठ फैला रहे हैं. बीजेपी और कांग्रेस वालों! जान लो- आतिशी सिंह है उसका पूरा नाम. राजपूतानी है. पक्की क्षत्राणी...झांसी की रानी है. बच के रहना. जीतेगी भी और इतिहास भी बनाएगी.' 2019 चुनाव में आतिशी तीसरे नंबर पर रही थीं और बीजेपी की टिकट पर गौतम गंभीर चुनाव जीते थे. हालांकि, इसके बाद आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर भी अपना सरनेम हटा दिया.

झारखंड और महाराष्ट्र
आसन्न विधानसभा चुनाव

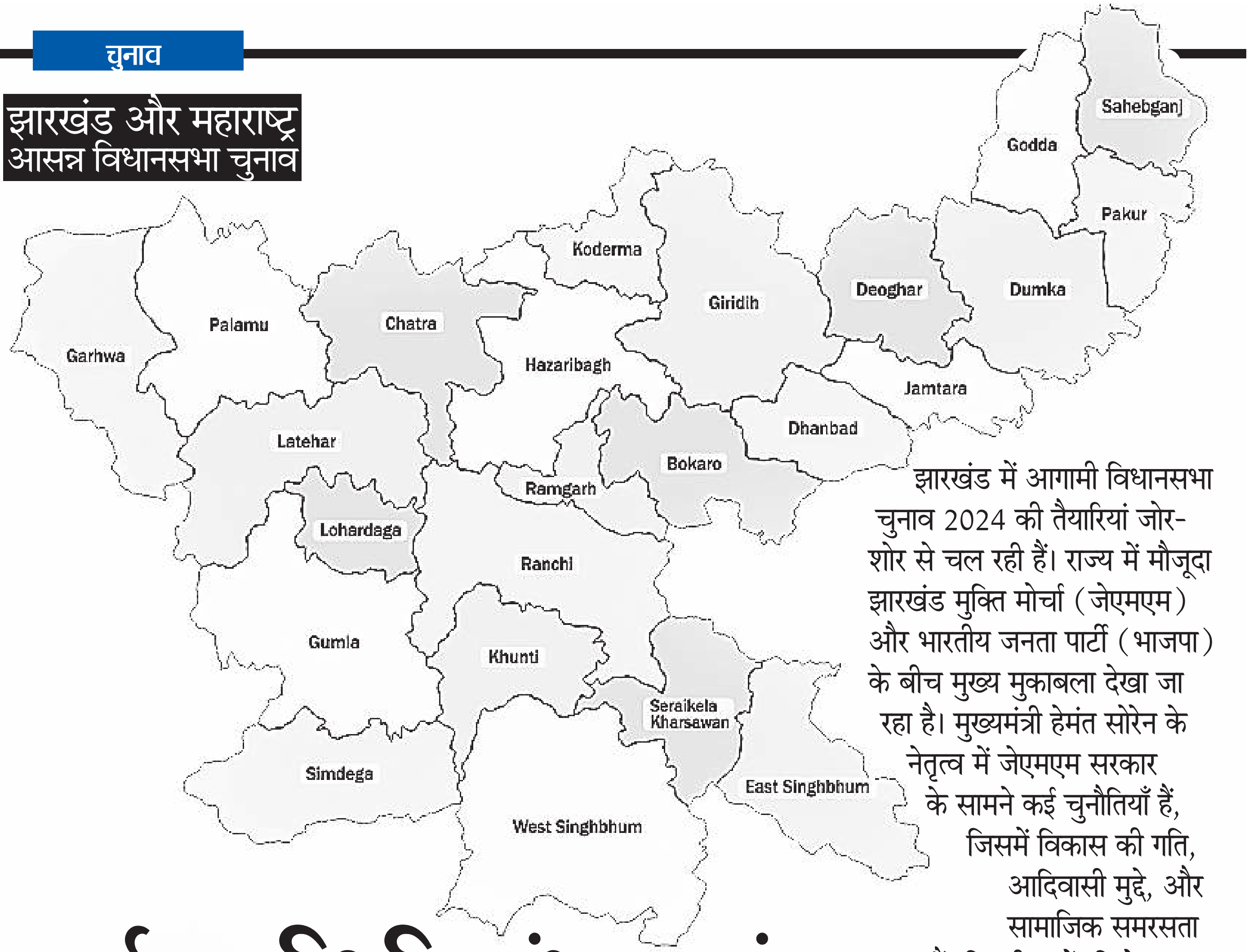

झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। राज्य में मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम सरकार के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जिसमें विकास की गति, आदिवासी मुद्दे, और सामाजिक समरसता प्रमुख हैं। विपक्षी दलों, विशेषकर भाजपा., कांग्रेस, और आजसू पार्टी ने अपने चुनावी मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है।

वर्तमान स्थिति, संभावनाएं और दलों के लाभ-हानियां

1. झारखंड मुक्ति मोर्चा

लाभ- हेमंत सोरेन की मौजूदा सरकार ने कई आदिवासी केंद्रित योजनाओं और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। पार्टी को आदिवासी वोट बैंक में मजबूत समर्थन प्राप्त है।
हानियाँ- विकास की गति धीमी रही है और कुछ मुद्दों पर सरकार की आलोचना की गई है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। इन मुद्दों को ठीक करने में असफलता पार्टी की चुनौतियों में शामिल हो सकती है।

2. भारतीय जनता पार्टी

लाभ- भाजपा ने राज्य में विकास और सुशासन का एजेंडा पेश किया है। पार्टी ने बड़े पैमाने पर चुनावी प्रचार और संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया है।
हानियाँ- आदिवासी मुद्दों और स्थानीय नेताओं के समर्थन की कमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा, राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन पार्टी के लिए नकारात्मक हो सकता है।

3. कांग्रेस

लाभ- कांग्रेस ने कुछ स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की है।
हानियाँ- कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर स्थिति और झारखंड में प्रभावी नेतृत्व की कमी पार्टी की समस्याओं में शामिल है।

4.आजसू पार्टी

लाभ- आजसू पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और विकास के एजेंडे को जोरदार तरीके से उठाया है।
हानियाँ- आजसू पार्टी के लिए प्रमुख चुनौती यह है कि पार्टी को बड़े राजनीतिक गठबंधन में शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है, जो उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी चल रही हैं। राज्य की राजनीति में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख दल हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिंदे सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी गुट और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है।

1. शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट)

लाभ- शिंदे गुट ने सरकार गठन के बाद कई विकास परियोजनाओं और लोकल मुद्दों को उठाया है। शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक का समर्थन भी इस गुट को मिल सकता है।

हानियाँ- शिंदे गुट के अंदरूनी विवाद और ठाकरे गुट के साथ टकराव, पार्टी की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं।

2. भारतीय जनता पार्टी

लाभ- भाजपा ने महाराष्ट्र में विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। पार्टी का केंद्र सरकार से समर्थन भी उसे लाभकारी स्थिति में रख सकता है।

हानियाँ- राज्य में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, स्थानीय मुद्दे और विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

3. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

लाभ- एनसीपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। पार्टी की स्थिर स्थिति और मजबूत स्थानीय नेतृत्व उसे लाभ दे सकता है।

हानियाँ- एनसीपी की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और गठबंधन के मुद्दे पार्टी के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

4. कांग्रेस

लाभ- कांग्रेस ने राज्य में सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी की स्थानीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

हानियाँ- कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर स्थिति और गठबंधन की चुनौतियां पार्टी के लिए समस्या हो सकती हैं।

चंपई सोरेन की भाजपा में शामिल होने का प्रभावः

चंपई सोरेन, जो झारखंड में एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं, का भाजपा में शामिल होना भाजपा के लिए एक रणनीतिक लाभ हो सकता है। सोरेन का आदिवासी समुदाय में प्रभाव और समर्थन भाजपा की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इससे भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, और पार्टी को झारखंड में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सोरेन का भाजपा में शामिल होना विपक्षी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इससे झारखंड की राजनीति में नए समीकरण उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्षः

झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की दिशा और परिणाम विभिन्न दलों की रणनीतियों, स्थानीय मुद्दों, और विकासात्मक एजेंडों पर निर्भर करेंगे। प्रत्येक पार्टी के लाभ और हानियाँ उसकी चुनावी सफलता को प्रभावित करेंगी। चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है और इसे विभिन्न दलों के लिए रणनीतिक लाभ या नुकसान का कारण बना सकता है। चुनावी परिदृश्य में लगातार बदलाव और नई रणनीतियों से दोनों राज्यों की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं।

'सरना धर्म कोड' का जिन्न फिर बाहर निकला

▪ नीरज सिन्हा

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग 'सरना धर्म कोड' को नए सिरे से उछाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार से उनकी मंशा पर सवाल किए हैं।

जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम निर्धारित करने की यह मांग उनकी भावना और पहचान से जुड़ी है। झारखंड में इस मांग को लेकर अलग-अलग आदिवासी संगठन लगातार आंदोलन करते रहे हैं। कई दफा दिल्ली में भी आदिवासी जुटान के साथ इस मुद्दे पर आवाज मुखर की गई है। जाहिर तौर पर यह मुद्दा बहस और राजनीति के केंद्र में भी रहा है।

लोकसभा चुनावों में भी यह मुद्दा आदिवासी इलाकों में सतह पर था। साथ ही सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिशें की थीं।

पांच सितंबर को झारखंड में आदिवासी बहुल गुमला जिले के सिसई ब्लॉक स्थित पंडरानी गांव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, "आज देश की सूची में आदिवासियों की पहचान आदिवासियों की नहीं है। इसलिए झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर सरना धर्म कोड मिल जाए, या आदिवासियों के लिए कोई कोड मिल जाए, तो आदिवासी सुरक्षित हो जाएंगे।"

हेमंत सोरेन ने इसी सभा में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है। दूसरे राज्यों से नेताओं को बुलाकर बीजेपी राज्य का माहौल खराब करने में लगी है।

पिछले 23 जून को पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में माझी परगना महाल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी कहा था कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने पहले ही अड़चनों को दूर कर दिया है, लेकिन केंद्र ने साजिश के तहत इसे लटकाए रखा है। चंपाई सोरेन हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं।

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में एक विशेष सत्र में 'सरना आदिवासी धर्म' कोड' का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा है।

पिछले साल इसी मामले में हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने कहा- देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रकृति पूजा आदिवासी/सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है।---

पत्र में आगे सोरेन ने कहा कि "झारखंड की आदिवासी आबादी पिछले आठ दशकों में 38 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत रह गई है और इसका संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ...यह सिर्फ झारखंड के ही नहीं– देश भर के आदिवासी कई सालों से अलग सरना/प्रकृति पूजा कोड की मांग कर रहे हैं।"

क्यों चाहते हैं एक अलग कोड?

जनगणना में अभी तक केवल हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के पास अपनी अलग संहिता या कोड है। आदिवासी मामलों के कई जानकारों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों का दावा है कि कोई अलग संहिता न होने के बावजूद 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने सरना को अपने धर्म के रूप में दर्ज कराया।

प्रकृति-उपासक सरना धर्म का पालन करते हैं। जल, जंगल और जमीन- प्रकृति के ये तीन पहलू सरना आस्था के मूल हैं। आदिवासी गांवों में जो पूजा स्थल होता है, उसे सरना स्थल कहते हैं। वहां मुख्यतः साल पेड़ की या फिर अन्य किसी पेड़ की पूजा की जाती है।

इसके साथ ही प्रकृति पूजा पर केंद्रित, सरना धर्म का मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों

द्वारा पालन किया जाता है। 2011 के जनगणना के मुताबिक झारखंड में जनजातीय आबादी 86.45 लाख (26.2) प्रतिशत है।

एक अलग सरना कोड का समर्थन करने वालों का तर्क रहा है कि यह आदिवासियों की भावना, पहचान परंपराओं और उनके धर्म की रक्षा करने के अलावा धर्मांतरण को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आदिवासी मुंडा दिशुम पड़हा समिति खूंटी के अध्यक्ष महादेव मुंडा कहते हैं, "पूर्वज और प्रकृति ही हमारे देवता हैं और जीवन के पालनहार भी। सरना धर्म कोड की मांग आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा मसला है। 1951 से पहले जनगणना में आदिवासियों की पहचान होती थी, लेकिन उसके बाद क्यों हटाया गया। हेमंत सोरेन जायज मांग उठाते रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती।"

'शून्यकाल में आदिवासी ' के लेखक अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं कि 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासी धर्म का एक अलग कॉलम था और पूछते हैं कि जब संविधान सभी धर्मों और भाषाओं के संरक्षण और सम्मान की बात करता है तो इसे क्यों हटा दिया गया।

पूर्वी सिंहभूम के देस पोरेनिक (पारंपरिक माझी परगना स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारी) दुर्गा चरण माझी कहते हैं,

हमारे लिए यह राजनीतिक नहीं, पारंपरिक रीति-रिवाज, संस्कृति और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। हम 20 साल से आवाज उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इस पर सहमत नहीं है और न ही इसने कोई मंशा उजागर की है।

***दुर्गा चरण माझी,** देस पोरेनिक, पूर्वी सिंहभूम

राजनीतिक मायने और असर

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रजत कुमार गुप्ता कहते हैं, "लोकसभा चुनावों में भी आदिवासी इलाकों में यह मुद्दा सतह पर था। जेएमएम- कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी को घेर रहे थे। लोकसभा चुनावों में राज्य में आदिवासियों की सभी पांच सीटों पर जीत के बाद जेएमएम- कांग्रेस विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को कॉर्नर करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के सांसद केंद्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर कितनी आवाज मुखर करते हैं, यह भी परखा जाना है।"

हालांकि पिछले 22 जुलाई को लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने भी लोकसभा में केंद्र सरकार से जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है।

सुखदेव भगत ने लोकसभा में कहा था, "ये अत्यंत संवेदनशील तथा आदिवासी अस्मिता का सवाल है। देश में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। लेकिन जनगणना में आदिवासियों के लिए कोई कॉलम निर्धारित नहीं करना हमारी मौलिक अधिकारों का हनन जैसा है। सरकार बाघ, शेरों की गणना करती है, तो प्रकृति पुजारियों की गणना क्यों नहीं की जानी चाहिए। यह विडंबना ही है।"

गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के दौरान 4 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के लोहरदगा दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर जयराम नरेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने आदिवासी हितों को लेकर कई सवाल किए थे। इन सवालों में उन्होंने यह भी कहा था कि आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान- सरना कोड को मान्यता देने से वंचित क्यों रखा गया है?

दूसरी तरफ भाजपा के नेता लगातार इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि पार्टी के लिए आदिवासियों का हित सर्वोपरि है, जबकि जेएमएम- कांग्रेस आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। लोकसभा चुनावों में भी सत्तारूढ़ दलों ने कई मुद्दे पर आदिवासियों को गुमराह किया था।

झारखंड में नवंबर- दिसंबर में चुनाव संभावित है। 2019 में सत्ता पर काबिज होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा- कांग्रेस (कंबाइन) बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरा है। 81 सदस्यीय विधानसभा में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटें हैं। ये सभी सीटें संथाल परगना, कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में हैं। इनके अलावा कम से कम 12 दूसरी सीटों पर भी आदिवासियों का वोट एक अहम फैक्टर रहा है।

2019 के चुनाव में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए रिजर्व सिर्फ दो सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलने में इस समीकरण को प्रभावी माना गया। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ संथाल परगना और कोल्हान में जेएमएम के गढ़ में दरक लगाने के लिए बीजेपी परेशान रही है।

घाटशिला से जेएमएम के विधायक और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री रामदास सोरेन कहते हैं, "जेएमएम के लिए यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। आदिवासियों के हक और अधिकार का सवाल है। चार साल पहले हेमंत सोरेन सरकार ने प्रस्ताव पास किया, तो बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों को बताना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। विधानसभा चुनाव को लेकर बाहर से आने वाले बीजेपी के उन नेताओं को भी इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, जो कई किस्म की राजनीतिक तिकड़म सजाते हैं।"

भारत की सबसे गहरी कोयला खदान मूनीडीह में उतरे कोयला राज्य मंत्री दुबे

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे पिछले दिनों भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के दौरे के तहत धनबाद में मूनीडीह भूमिगत कोयला खदान का निरीक्षण किया। यह खदान भारत की सबसे गहरी कोयला खदानों में से एक है।

इस दौरान श्री दुबे ने खनिकों से मुलाकात की और उन्हें देश को ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सराहा। कोयला राज्य मंत्री ने खदान के संचालन का भी गहन निरीक्षण किया। सुरक्षा प्रोटोकॉल और दक्षता उपायों के बारे में जानकारी ली।

मंत्री ने तकनीकी प्रगति और परिचालन प्रथाओं पर एक वीडियो प्रस्तुति भी देखी। इस दौरान उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत दो महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे ने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है, और हम एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य के लिएउनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सिजुआ क्षेत्र पहुंचे : कोयला राज्य मंत्री ने सतही बुनियादी ढांचे पर कोयला खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सिजुआ क्षेत्र (बीसीसीएल) के सेंद्रा बांसजोरा में अवतलन स्थल का दौरा किया। स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया और अवतलन मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है जिससे हम पर्यावरण और सामुदायिक कल्याण के साथ खनन कार्यों को संतुलित करना जारी रख सकें।

कोयला राज्य मंत्री ने स्थिति की गंभीरता का आकलन किया और नुकसान को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और आस-पास के समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना भी। श्री दुबे ने कहा कि हम आग को नियंत्रित करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने और भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक समाधान लागू करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस चुनौती पर काबू पाने में अधिकारियों और कोयला श्रमिकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

इसके पहले कोयला राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे के बीसीसीएल आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्री ने कोयला नगर स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे ने अपने संदेश में कहा धनबाद में मूनीडीह भूमिगत कोयला खदान का दौरा करने का अवसर मिला, जो भारत की सबसे गहरी कोयला खदानों में से एक है।इस दौरान, मैंने उन मेहनती खनिकों से मुलाकात की जो देश को ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने खदान के संचालन का भी गहन निरीक्षण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और दक्षता उपायों को बनाए रखा जा रहा है।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है, और हम एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

117 साल पुरानी एना कोलियरी का लिया जायजा

कोयला एवं खान राज्य मंत्री, सतीश चन्द्र दुबे ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की एना कोलियरी का जायजा लिया। सीएमडी ने कोयला राज्य मंत्री को उत्पादन आदि की जानकारी दी। इस दौरान सीआईएल चेयरमैन पीएम प्रसाद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एना कोलियरी में कोयला खनन का इतिहास 117 साल पुराना है जो 1906 से शुरू होता है। बीसीसीएल के कोयला उत्पादन में इस कोलियरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। 216 हेक्टेयर में फैली इस साइट में कुल 165.50 मिलियन टन का कोयला भंडार है। बीसीसीएल प्रबंधन ने जलते हुए कोयले को निकालने और गर्म ओवरबर्डन के सुरक्षित रूप से हटाने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रक्रियाओं को लागू करना सुनिश्चित किया है। अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों से कोयला निकालने की इन प्रक्रियाओं में निरंतर पानी का छिड़काव, गैर-दहनशील सामग्री से ब्लैंकेटिंग और कोयले को पूरी तरह से बुझाने की प्रक्रियाएं आदि शामिल हैं।

उत्पादन 384 मिलियन टन तक पहुंचा

कोयला मंत्रालय ने समग्र कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त 2024 तक 384.08 मिलियन टन (अंतिम) तक पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान यह 360.71 मिलियन टन था, जो 6.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन बढ़कर 290.39 मिलियन टन हो गया, जो पिछली वर्ष की इसी अवधि के दौरान 281.46 मीट्रिक टन की तुलना में 3.17 प्रतिशत की वृद्धि है। कैप्टिव और अन्य कंपनियों से भी कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो अप्रैल से अगस्त 2024 तक 68.99 मिलियन टन तक पहुंच गया – यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 52.84 मिलियन टन की तुलना में 30.56 प्रतिशत की एक अच्छी खासी वृद्धि है।

इस बीच, अगस्त 2024 तक संचयी कोयला प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अगस्त 2024 तक संचयी कोयला प्रेषण वित्त वर्ष 2024-25 में 412.07 मिलियन टन (अनंतिम) था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान 391.93 मिलियन टन था। यह 5.14 प्रतिशत की प्रशंसनीय योग्य वृद्धि को दर्शाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल से अगस्त 2024 तक 309.98 मिलियन टन कोयला भेजा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान भेजे गए 305.37 मिलियन टन की तुलना में 1.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, कैप्टिव और अन्य कंपनियों ने 76.95 मिलियन टन का उल्लेखनीय कोयला प्रेषण दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान भेजे गए 58.53 मिलियन टन की तुलना में 31.48 प्रतिशत की बहुत अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि कोयला क्षेत्र की बेहतर रसद क्षमताओं और कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

महत्वाकांक्षी परियोजना - 20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल, रांची का दौरा किया। रांची आगमन पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरे में मंत्री ने सबसे पहले बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा भगवान बिरसा मुंडा, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंडा जनजाति के लोकनायक को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद मंत्री ने सीसीएल के कार्य-कलापों का जायजा लिया जिसमें सीसीएल के सीएमडी, श्री निलेन्दु कुमार सिंह एवं निदेशक गण उपस्थित थे। मंत्री ने सीसीएल के उत्पादन, प्रेषण एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा की तथा उचित दिशा निर्देश दिए। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले के उत्पादन एवं प्रेषण में और बढ़ोत्तरी करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सीसीएल के साथ - साथ सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की।

इसके बाद श्री दुबे ने सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने सीसीएल के महत्वाकांक्षी परियोजना - 20 मेगावाट क्षमता के एक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस सोलर पावर प्लांट के माध्यम से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि सोलर पावर यानि सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश से ही सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका इस्तेमाल बिजली रहित इलाकों में बिजली पहुंचाने और घरेलू कामों में, जैसे - खाना पकाने इत्यादि में किया जा सकता है। इससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी कम होगा। ज्ञात हो कि प्रधान मंत्री के दिशानिर्देश पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में यह सोलर प्लांट काफी कारगर साबित होगा। इस दौरान उन्होंने वहां के अधिकारियों एवं हितधारकों से मिले। उन्होंने हितधारकों के समुचित विकास हेतु उचित और बहुमूल्य दिशा निर्देश भी दिए।

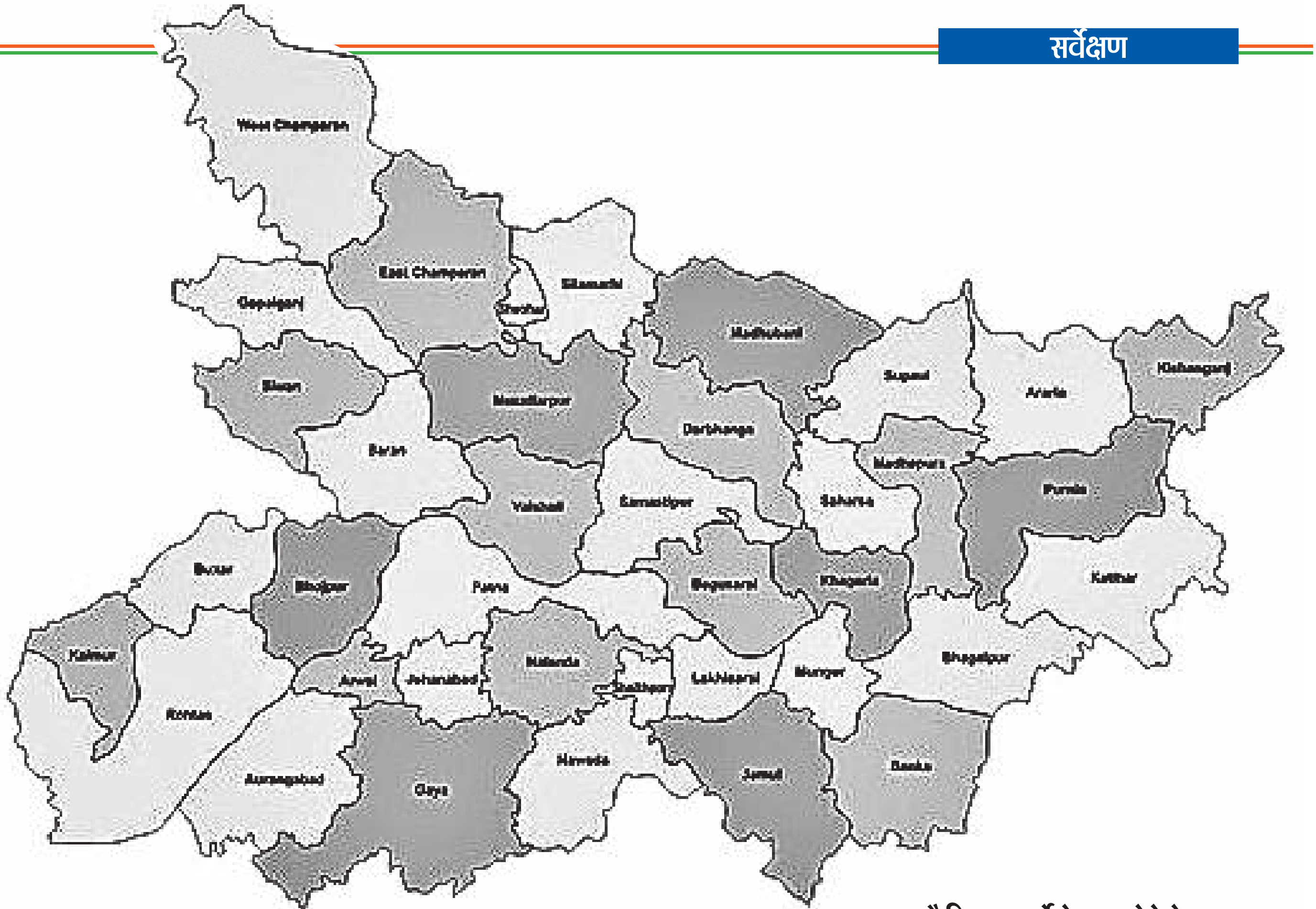

45,000 गांवों में जमीन का सर्वेक्षण

» राज्य सरकार का मानना है कि इस सर्वे के पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े विवाद के 95 प्रतिशत मामले कम हो जाएंगे

» बिहार में आजादी के पहले जमीन का सर्वे किया गया था, बाद में साठ के दशक में रिवाइज्ड सर्वे किया गया

▪ मनीष कुमार

बिहार के करीब 45,000 गांवों में इन दिनों जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है। कई चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया को जुलाई 2025 तक पूरा होना है। लेकिन, रोजी-रोटी कमाने के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोग इससे काफी परेशान हैं।

बिहार सरकार ने इसके लिए भू-स्वामियों को जमीन का मालिक होने के लिए सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज दिखाने को कहा है। और, इन्हीं दस्तावेजों को जुटाने में कई लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। खास तौर पर रोजी-रोटी के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोग काफी पसोपेश में हैं। लोगों में यह डर भी है कि अगर वांछित दस्तावेज नहीं दिखा सके तो उनकी जमीन कहीं सरकार की तो नहीं हो जाएगी। हालांकि, सरकार सर्वेक्षण के संबंध में पूरी प्रक्रिया का सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार कर रही है।

ग्राम सभा में अधिकारी दे रहे सर्वे की जानकारी : सर्वे शुरू होने से पहले सभी पंचायतों में ग्राम सभाएं हो रही हैं। अधिकारी लोगों को यह बता रहे कि जमीन पर दावा करने के लिए उन्हें कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज इस बात पर निर्भर होंगे कि जमीन किस श्रेणी की है तथा किसके नाम पर है। अगर यह पूर्वजों के नाम पर है तो उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा, मालगुजारी रसीद और खतियान (ऐसा अधिकार अभिलेख जिसमें रकबा समेत जमीन की पूरी जानकारी होती है) की कॉपी दिखानी होगी। यदि दान की है या जमींदार द्वारा बंदोबस्त की गई है तो फिर दान पत्र या बंदोबस्त से संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा। स्व-घोषणा पत्र के साथ वंशावली या आपसी बंटवारा से संबंधित कागजात भी देना होगा। जिस जमीन पर दावा किया जा रहा है, उस भूखंड की चौहद्दी भी दर्ज करनी होगी।

जरूरत के अनुसार इन दस्तावेजों को गांवों में लगने वाले शिविर में या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके बाद सर्वे कर्मी भूखंड पर जाकर ऑन स्पॉट जांच करेंगे, उस वक्त जमीन मालिक या उसके प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। अगर, उस वक्त किसी और ने दावा कर दिया तो उसे भी दर्ज किया जाएगा, जिसकी बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा जांच की जाएगी। तय अवधि के बीच किसी तरह की आपत्ति नहीं होने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद अंत में जमीन उसके वर्तमान मालिक के नाम पर दर्ज हो जाएगा। इससे जुड़ी विशेष जानकारी बिहार सरकार के भू-राजस्व विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सर्वे के चरणबद्ध प्रावधानों या प्रक्रियाओं की अपडेट स्थिति जानने के लिए बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप भी बनाया है।

बिहार में आजादी के पहले जमीन का सर्वे किया गया था, बाद में साठ के दशक में रिवाइज्ड सर्वे किया गया। हालांकि, यह पूरा नहीं हो पाया। सरकार के पास कोई अपडेट रिकॉर्ड नहीं है कि उसका वर्तमान मालिक कौन है। लोगों के दादा-परदादा के नाम से जमीन है और उन्हीं के नाम से भू-लगान की रसीद कट रही है।

अवकाश प्राप्त अधिकारी राजशेखर शरण कहते हैं, "बिहार में अब भी जो खतियान इस्तेमाल में है, वह काफी पुराना है। अधिकतर जगहों पर यह 1910 तक का बना हुआ है। जब यह पुराना हो जाता है तो इसके कई दावेदार हो जाते हैं क्योंकि तब तक परिवार कई हिस्सों में बंट चुका होता है। किंतु उनके नाम पर कुछ होता नहीं है। दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है।"

खतियान जिसके नाम से है, वहां से लेकर अब तक की वंशावली बनाने से समाधान निकल सकता है किंतु अगर किसी पक्ष को आपत्ति हुई तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है। कई जमीनें ऐसी हैं, जिनका खाता-खेसरा तक गायब है। बिहार जैसे राज्य में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गोपालगंज के किसान देवेंद्र राय कहते हैं, "मेरे पास तो

दादा के नाम वाली रसीद है। पिता जी के पास भी कुछ नहीं था। बाढ़ आने पर जान बचाना मुश्किल होता है, पहले लोग जान बचाए कि सामान की चिंता करें। पता नहीं किस बक्से में कौन-कौन कागज कब बह गया होगा।"

इसके अलावा टोपोलैंड अर्थात नदियों के किनारे की वैसी जमीन जो धारा बदलने के कारण बाहर आ गई और किसान उस पर फसल उगाने लगे। इसे वे अपने पूर्वजों की जमीन बताते हैं, जो समय के साथ नदी में समा गई और कालांतर में फिर बाहर आ गई। दियारे की ऐसी जमीनों का अब तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इन किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें।

चिंता की बड़ी वजह मौखिक बंटवारा : बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है। आशय यह कि परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुरूप कागज पर उनके बीच पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं किया गया है। उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। सर्वे के लिए मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। अब इसके लिए सभी भाइयों व बहनों के हस्ताक्षर वाला कागजात (पेपर) तैयार करना होगा। यदि किसी भाई या बहन की मौत हो चुकी है तो उसके सभी बच्चे बंटवारे के उस पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे। जाहिर है, ऐसे लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है।

इसके साथ एक और भी समस्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने तीन बेटों के बीच जमीन का मौखिक बंटवारा किया था और अब उसकी मौत हो चुकी है। कालांतर में दो भाइयों ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी तो तीसरे भाई को बंटवारा के पेपर पर उन दोनों भाइयों के

> **बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है।**

हस्ताक्षर भी लेने होंगे। सर्वे अधिकारी यह नहीं देखेंगे कि किस भाई ने जमीन बेची और किसने नहीं। पिता के नाम पर जितनी जमीन बची होगी, उसके संयुक्त खतियान में तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा। जाहिर है, यह फसाद की जड़ बनेगा।

एक बार अगर सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो डिजिटल होने के कारण जमीन का रिकॉर्ड यथासंभव पारदर्शी हो जाएगा तथा यह पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। इससे खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी की आशंका भी कम हो जाएगी, साथ ही प्रदेश में अपराध के ग्राफ और अदालतों में मुकदमों के बोझ में खासी कमी आ जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि इस सर्वे के पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े विवाद के 95 प्रतिशत मामले कम हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में सर्वाधिक हत्या भूमि विवाद में होती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण जमीन की नाप-जोख की तथा कागजातों की गड़बड़ी है। इसके साथ ही सरकार अपनी जमीन यानी गैरमजरूआ आम (खतियान के आधार पर जिसका निजी स्वामित्व नहीं है) की पहचान कर उसे अतिक्रमण मुक्त करा सकेगी। सही, स्पष्ट और अपडेट रिकॉर्ड होने से सरकार को कृषि, सिंचाई, पशुपालन व अन्य योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। विकास योजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण में भी आसानी होगी।

बड़ी आबादी डिजिटल दुनिया से दूर : भू-राजस्व विभाग का अधिकतर कामकाज ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि एक बड़ी आबादी आज भी डिजिटल दुनिया से अपरिचित हैं। ऐसे लोगों के लिए दाखिल-खारिज, जमीन का नक्शा प्राप्त करने व भू-लगान की रसीद कटवाने जैसे काम दुरूह साबित हो रहे। बकाया लगान जमा करने पर सरकार ने किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया है, किंतु साइबर कैफे वाले जुर्माना के नाम पर वसूली कर रहे।

अधिवक्ता राजेश के सिंह कहते हैं, "सर्वे की पूरी प्रक्रिया जितनी आसान कही जा रही है, उतनी है नहीं। प्रोसेस भी काफी लंबा है। कई तरह की अन्य समस्याएं हैं। भू-राजस्व विभाग की सच्चाई सभी जानते हैं, ऐसे में कागजात जुटाने में लोगों को कितनी मदद मिलेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।"

आम बिहारी कागजातों के लिए ब्लॉक कार्यालयों का चक्कर लगाने तथा भू-राजस्व विभाग के कर्मियों से साक्षात्कार को किसी सजा से कमतर नहीं मानता। इस विभाग के मंत्री ने भी कुछ दिनों पहले यह स्वीकार किया था कि उनका विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और यहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। फिलहाल, सुकून की बात है कि भू-राजस्व मंत्री डा। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सर्वे में कहीं भ्रष्टाचार की बात दिखे तो सीधे उन्हें फोन या मेल पर सूचित करें।

पीएम जनमन आवास योजना से दो पीढ़ियों का सपना हुआ साकार

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कसडोल विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे वनांचल ग्राम बल्दाकछार निवासी 76 वर्षीय चंदा बाई कमार और उनके पति मंगल सिंह कमार का जीवन काफी संघर्षमय रहा। पक्का मकान तो उनके लिए एक सपने की तरह था, लेकिन पीएम जन मन आवास योजना से आज उनका खुद का पक्का मकान बन गया है। वे कहते हैं कि, उनके संघर्षपूर्ण जीवन का अंत और दो पीढ़ियों का सपना आज पीएम जनमन आवास योजना से पूरी हुई है।

बहू का परिवार भी हुआ लाभान्वित

श्रीमती चंदा बाई कमार की बहू श्रीमती बुधार बाई कमार ने दो साल पहले किशुन लाल से शादी की थी। हालांकि कुछ समय बाद वे अलग होकर अपने परिवार के साथ रहने लगीं। बुधार बाई और उनके पति बांस से झाड़ू,टुकना, सूपा आदि बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके दो बच्चे हैं बेटी बबली जो कक्षा 7वीं में पढ़ रही है और बेटा शिवम जो अभी सिर्फ एक साल का है। बुधार बाई का परिवार भी पीएम जनमन आवास योजना से लाभान्वित हुआ है। इस योजना के तहत उन्हें भी पक्का मकान मिला। जिससे उनका जीवन अब और अधिक खुशहाल हो गया। अब बुधार बाई अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित और सुंदर घर में रहती हैं। वह कहती हैं 'इस योजना ने हमें न सिर्फ छत दी बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और सम्मान भी दिया।'

जिंदगी भर मजदूरी करके जैसे-तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करने वाले इस दंपत्ति के पास इतने साधन नहीं थे कि, वे खुद का पक्का मकान बना सकें। बरसों से झोपड़ी में रहते हुए उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। एक सपना हमेशा उनके दिल में जिंदा था, अपने पक्के मकान का सपना। हालांकि वक्त ने एक नया मोड़ तब लिया जब पीएम जनमन आवास योजना के तहत उन्हें अपना पक्का मकान बनाने का मौका मिला। चंदा बाई और उनके पति के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं थी। अब वे एक सुरक्षित और पक्के घर में रहने का सपना पूरा होते देख पा रहे हैं। चंदा बाई कहती हैं- 'हमने कभी सोचा भी नहीं था कि, इस उम्र में हम अपना खुद का मकान देख सकेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हमारा सपना सच कर दिखाया है।

दो पीढ़ियों का सपना हुआ पूरा : चंदा बाई और बुधार बाई दोनों की कहानी यह साबित करती है कि, पीएम जनमन आवास योजना ने केवल मकान ही नहीं बल्कि उनके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान भी लाया है। सास और बहू दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि, उनके सपनों को हकीकत में बदलने में यह योजना मील का पत्थर साबित हुई है। चंदा बाई ने गर्व के साथ कहा, इस उम्र में अपने खुद के घर में रहना हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, हमे दो पीढ़ी बाद पक्का घर मिला। वहीं बुधार बाई ने कहा यह योजना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव है।

सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले- कांग्रेस ने 18 लाख लोगों का हक छीना

छत्तीसगढ़ में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिल गई है। जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता में कहा कि, प्रदेश के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। पिछले पांच साल में कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास को रोककर रखा था। उसे स्वीकृति मिल गई है। सीएम श्री साय ने कहा कि, प्रदेश के लोगों के लिए खुशी का दिन है। पिछले पांच साल कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास को रोककर रखा था। जिसमें 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय न मिले इसलिए 18 लाख लोगों का हक छिना गया था। पीएम मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि, पहला सीएम जो भी बनेगा वह पीएम आवास की घोषणा करेगा। जिसके बाद हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने आगे कहा कि, नए वित्तीय वर्ष में 8 लाख 46 हजार आवास की स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के लिए मैं पीएम मोदी को आभार व्यक्त करता हूं। पिछली कांग्रेस सरकार में 47 हजार आवास की स्वीकृति दे दी गई थी। पहली किस्त भी इन परिवारों को जारी की गई थी। सरकार इन परिवारों को भी दूसरी किस्त देने जा रही है। किसी परिवार के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और नीयद नेल्लानार के तहत पीड़ित परिवारों को पीएम आवास हम देंगे।

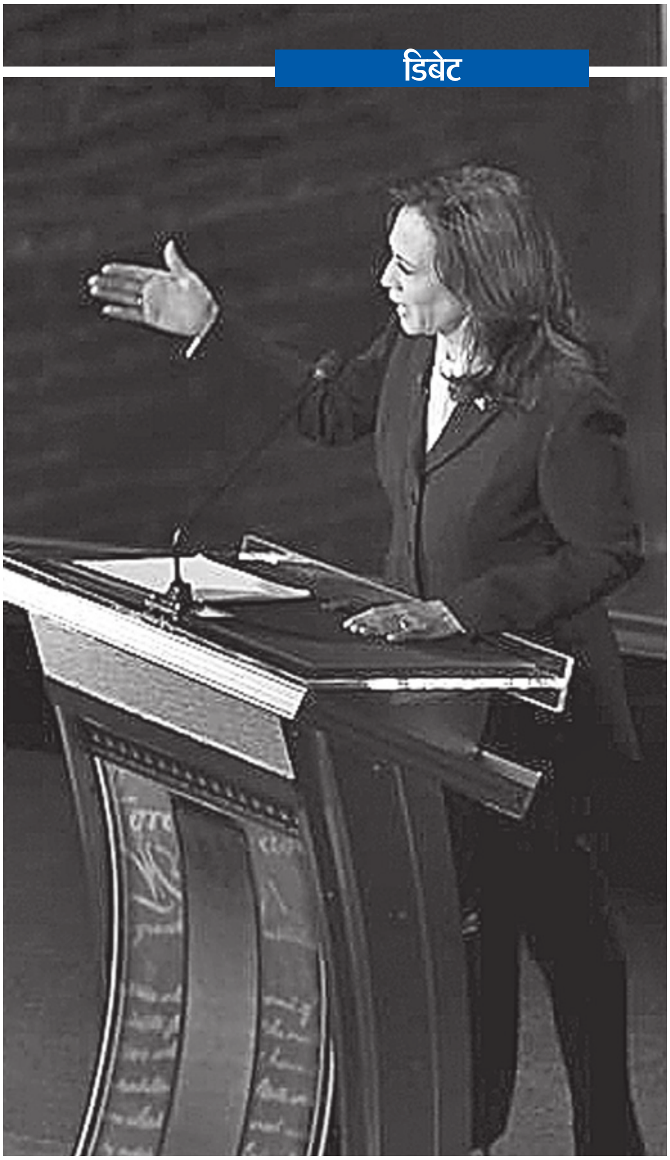

हैरिस-ट्रंप डिबेट: कौन जीता, कौन हारा

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों कमला हैरिस और डॉनल्ड ट्रंप के बीच हुई पहली बहस का 5 नवंबर को होने वाले चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है. इस बात पर चर्चा हो रही है कि दोनों उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा.

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस और डॉनल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस से पहले यह सवाल था कि हैरिस और ट्रंप, जो पहले कभी नहीं मिले थे, एक-दूसरे से कैसे मिलेंगे. कमला हैरिस ने इस सवाल का जवाब तय किया. बहस शुरू होने से पहले वह ट्रंप के पास गईं और मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया. विश्लेषकों के मुताबिक इस कदम के साथ ही हैरिस ने बहस में एक बढ़त हासिल कर ली क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप उनके रंग, नस्ल और लिंग को लेकर तीखी और कड़वी टिप्पणियां करते रहे हैं. शुरुआत से ही बहस उन मुद्दों पर मुड़ गई, जिन पर अमेरिकी मतदाताओं के बीच गहरा विभाजन है. हैरिस ने बहस के दौरान खुद को भविष्य की ओर देखने वाली एक प्रगतिशील उम्मीदवार के रूप में पेश किया. उन्होंने भविष्यवाणी की कि ट्रंप बहस में "वही पुरानी घिसी-पिटी लीक" पर चलेंगे. हैरिस ने कहा,

एक-दूसरे को उकसाने की कोशिश

बहस की शुरुआत में कमला हैरिस ने इरादा जाहिर कर दिया कि वह डॉनल्ड ट्रंप को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर करेंगी. उन्होंने ट्रंप को उकसाने की पूरी कोशिश की और उन्हें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया. उन्होंने दर्शकों से कहा कि वे ट्रंप की रैलियों में शामिल हों जहां उन्हें अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे कि पवनचक्कियां कैंसर का कारण बनती हैं (एक ऐसा दावा जो ट्रंप ने वास्तव में किया था). हैरिस ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि रैली में भाग लेने वाले थकावट और बोरियत से बाहर निकल जाएंगे. अपनी रैलियों में बड़ी भीड़ जमा करने को खूब गर्व से कहने वाले ट्रंप इस टिप्पणी से साफ तौर पर चिढ़ गए. उन्होंने कहा, "हमारी रैलियां सबसे बड़ी रैलियां होती हैं. राजनीति के इतिहास की सबसे अविश्वसनीय रैलियां होती हैं." उन्होंने हैरिस पर आरोप लगाया कि वे अपनी रैलियों में उपस्थित लोगों को बसों से लाती हैं. इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि ओहायो के स्प्रिंगफील्ड शहर में अवैध प्रवासी लोगों के पालतू जानवरों को मारकर खा रहे हैं. यह एक असत्यापित दावा है जो सोशल मीडिया पर साझा हुआ है और जिसे ट्रंप के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वैंस ने भी दोहराया है. ट्रंप ने कहा, "स्प्रिंगफील्ड में वे कुत्तों को खा रहे हैं. जो लोग वहां आए हैं, वे बिल्लियों को खा रहे हैं. वे वहां रहने वाले लोगों के पालतू जानवरों को खा रहे हैं." स्प्रिंगफील्ड के अधिकारियों ने कहा है कि ये रिपोर्टें झूठी हैं. बहस के दौरान एबीसी चैनल के मॉडरेटरों ने ट्रंप की टिप्पणियों के बाद इस बात को स्पष्ट भी किया.

"झूठ, शिकायतें और गालियों का भंडार."

आक्रामक रणनीति, तीखी तकरार : ट्रंप को उनके पिछले रिकॉर्ड के लिए घेरना, कैलिफॉर्निया में वकालत कर चुकीं हैरिस की रणनीति रही. उन्होंने खास तौर पर ट्रंप को 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने के प्रयासों के लिए घेरा. बहस के एक घंटे बाद, उनकी रणनीति सफल होती दिख रही थी. ट्रंप लगातार रक्षात्मक स्थिति में थे. 6 जनवरी 2021 को कैपिटोल इमारत पर हुए हमले के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने जोर देकर कहा कि "उसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने मुझसे एक भाषण देने के लिए कहा था." उन्होंने यह भी झूठा दावा किया कि उन्होंने 2020 का चुनाव जीता था. हैरिस ने ट्रंप के कामों का जिक्र करते हुए देश से आग्रह किया कि अब नया अध्याय शुरू करने का समय है. उन्होंने कहा, "डॉनल्ड ट्रंप को 8.1 करोड़ लोगों ने हटा दिया था, तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए. और जाहिर है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं कर सकते जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मतदाताओं की इच्छा को पलटने का प्रयास करे."

उपराष्ट्रपति हैरिस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर थोड़ी और चोट करते हुए कहा कि दुनियाभर के नेता "उन पर हंस रहे हैं" और उन्हें "अपमानजनक" कह रहे हैं. ऐसे शब्द ट्रंप ने खुद राष्ट्रपति जो बाइडन के बारे में रैलियों में इस्तेमाल किए हैं.

कुछ मिनटों बाद ट्रंप भड़क गए. उन्होंने दावा किया कि हैरिस को डेमोक्रैटिक नामांकन के लिए "कोई वोट" नहीं मिले थे और उन्होंने किसी तरह के तख्तापलट के जरिए बाइडन की जगह ली. उन्होंने कहा कि जो बाइडेन "उनसे (हैरिस से) नफरत करते हैं."

कई मुद्दों पर बहस : बहस के शुरुआती मिनटों में, ट्रंप और हैरिस ने मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चर्चा की. हैरिस ने हाल के हफ्तों में अपनी आर्थिक नीतियों का ब्यौरा दिया, जिनमें छोटे स्टार्ट-अप के लिए एक महत्वपूर्ण टैक्स क्रेडिट स्थापित करना शामिल है. ट्रंप ने अपने बयानों में टैरिफ पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाएंगे.

ट्रंप की शुरुआती टिप्पणियों के बाद हैरिस ने कहा, "उनके पास कोई योजना नहीं है. यह ऐसा है जैसे दौड़ो, स्पॉट, दौड़ो."

दोनों उम्मीदवारों के बीच गर्भपात पर एक तीखी बहस हुई. यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे लेकर सर्वेक्षणों के अनुसार हैरिस को ज्यादा मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ है. ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2022 के उस फैसले का बचाव किया, जिसके जरिए गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा समाप्त कर दी गई और इसे राज्य सरकारों के हाथों में सौंप दिया गया. उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला रिपब्लिकन और डेमोक्रैट्स दोनों ही पक्ष के लोग चाहते थे. लेकिन यह एक गलत दावा है क्योंकि डेमोक्रैटिक पार्टी ने हमेशा गर्भपात के संवैधानिक अधिकार का समर्थन किया है. ट्रंप ने कहा, "मैंने ऐसा करके महान सेवा की है. ऐसा करने के लिए साहस की जरूरत थी."

हैरिस ने गर्भपात को राज्य-अधिकारों का मुद्दा बनाने के ट्रंप के दावे पर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने वैसे राज्यों का हवाला दिया, जिन्होंने अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए हैं. उन्होंने कहा, "क्या लोग ऐसा चाहते थे? लोगों को अस्पतालों की इमरजेंसी में इलाज से वंचित किया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जेल जाने के खतरे से भयभीत हैं."

ट्रंप से पूछा गया कि अगर कांग्रेस द्वारा एक संघीय गर्भपात प्रतिबंध पारित किया गया तो क्या वह उस पर वीटो करेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन सवाल का स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया. इस गर्मागर्म बहस में, ट्रंप और हैरिस ने एक-दूसरे पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए न्याय विभाग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. ट्रंप ने कहा कि उनके खिलाफ 2020 की चुनावी हार को पलटने की साजिश रचने और गोपनीय दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने के लिए दायर आरोप और पोर्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी जैसे मामले हैरिस और बाइडेन द्वारा रची गई एक साजिश का नतीजा हैं. हैरिस ने तुरंत जवाब दिया, "मुझे लगता है कि जो व्यक्ति संविधान को समाप्त करने की इच्छा रखता है, उसे कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए."

बहस पर प्रतिक्रियाएं : बहस के बाद अमेरिका में दोनों नेताओं के प्रदर्शन पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं. अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली दक्षिण अमेरिकी मूल के कई नेताओं ने हैरिस के प्रदर्शन की सराहना की और "प्रवासी समुदायों के खिलाफ" ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की.

डेमोक्रैटिक रणनीतिकार मारिया कार्डोना ने हैरिस की प्रदर्शन को "राष्ट्रपति बहस में एक मास्टरक्लास" कहा. बहस के तुरंत बाद, लैटिनोज कॉन हैरिस-वॉल्ज वॉट्सऐप चैनल ने एक संदेश साझा किया: "जो बहुत बोलता है, कम कहता है. हम आपके बारे में जानते हैं, डॉनल्ड." संदेश को चैनल के सदस्यों से कई हंसती हुई इमोजी प्रतिक्रियाएं मिलीं. लीग ऑफ लैटिन अमेरिकन यूनाइटेड सिटीजन नामक संस्था के सीईओ हुआन प्रोआनो ने कहा कि बहस ने नीतिगत मुद्दों जैसे कि अर्थव्यवस्था और आप्रवासन पर बातचीत को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं की. प्रोआनो ने कहा कि हैरिस ने लैटिनो समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों को बेहतर ढंग से संबोधित किया, जबकि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी पर केंद्रित थे. ट्रंप समर्थक सीनेटर मार्को रुबियो ने बहस संचालित करने वाले एबीसी के मॉडरेटर की आलोचना की. फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो ने कहा कि महंगाई या हाइड्रॉलिक फ्रैक्चरिंग जैसे मुद्दों को लेकर हैरिस पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला गया. उन्होंने कहा, "मॉडरेटरों ने बहुत सारी चीजों पर सवाल नहीं पूछे." उन्होंने जोड़ा कि वह बहस के मॉडरेटर की अक्सर आलोचना नहीं करते, लेकिन इस मामले में ऐसा करना उचित था.

पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट ने बहस के तुरंत बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट में हैरिस का समर्थन किया. उन्होंने लिखा, "मैं 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस और टिम वॉल्ज के लिए अपना वोट डालूंगी. मैं कमला हैरिस के लिए वोट दे रही हूं क्योंकि वह उन अधिकारों और कारणों के लिए लड़ती हैं जिन्हें मैं मानती हूं और जिनके लिए एक योद्धा की जरूरत है."

खुद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बहस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, "लोग कह रहे हैं कि आज रात बड़ी जीत मिली है. मुझे लगता है कि यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी बहस थी, खासकर इसलिए, क्योंकि यह तीन बनाम एक थी."

बांग्लादेश ने रोका भारत को हिल्सा मछली का निर्यात

▪ प्रभाकर मणि तिवारी

हर साल दुर्गा पूजा के सीजन में बांग्लादेश से पद्मा नदी की हिल्सा मछलियां बंगाल पहुंचती थी. लेकिन इस बार अंतरिम सरकार ने 'मछलियों की रानी' कही जाने वाली इस मछली का निर्यात नहीं करने का फैसला किया है.

बंगालियों के लिए हिल्सा महज एक मछली नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है. बीते साल दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने 3,950 टन हिल्सा कोलकाता भेजी थी. दुनिया भर की कुल हिल्सा का 70 फीसदी उत्पादन बांग्लादेश में ही होता है. यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है.

पद्मा की हिल्सा में जो स्वाद होता है वह कहीं और मिलने वाली इस मछली में नहीं होता. यही वजह है कि हर साल खासकर दुर्गा पूजा के समय बंगाल के लोग सीमा पार से आने वाली इस मछली का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं. हिल्सा की कीमत इसके वजन से तय होती है. जितनी बड़ी मछली उतनी ही ज्यादा कीमत. करीब दो हजार रुपए प्रति किलो तक बिकने के बावजूद इसकी भारी मांग रहती है. यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि बंगाली समुदाय में कोई धार्मिक अवसर हो या सामाजिक, इस मछली के बिना अधूरा ही रहता है.

निर्यात पर पाबंदी क्यों : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कथित रूप से अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए इस साल भारत को हिल्सा के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है. मत्स्य पालन मंत्रालय में सलाहकार फरीदा अख्तर ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर भारत को इस मछली का निर्यात नहीं किया जाएगा.

इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय शुरू की गई परंपरा पर ब्रेक लग गया है. हसीना सत्ता में रहने के दौरान हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच सद्भावना के तौर पर भारी मात्रा में हिल्सा यहां भिजवाती थी.

हालांकि बांग्लादेश के सरकारी सूत्रों ने बताया कि घरेलू मांग तो एक बहाना है. दरअसल, शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद देश के आम लोगों में भड़की भारत विरोधी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने यह फैसला किया है. सरकार लोगों की भावनाओं को और भड़काने का खतरा नहीं उठाना चाहती.

बीते साल पद्मा की हिल्सा की पहली खेप पेट्रापोल सीमा चौकी से होकर बंगाल पहुंची थी. उस खेप में बरिशाल से कुल 45 टन मछली आई थी. उस साल बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने 79 निर्यातकों को करीब चार हजार टन मछली के निर्यात की अनुमति दी थी.

पहला मौका नही : बांग्लादेश की ओर से इस मछली के निर्यात पर पाबंदी लगाने का यह पहला मौका नहीं है. इससे पहले जुलाई, 2012 में भी कथित घरेलू मांग बढ़ने के कारण शेख हसीना सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी. माना जाता है कि उस समय भी पाबंदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये की वजह से ही लगी थी. उन्होंने तीस्ता के पानी पर प्रस्तावित समझौते पर नाराज होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बांग्लादेश दौरे पर जाने से मना कर दिया था.

इस पर पलटवार करते हुए बांग्लादेश ने हिल्सा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी. उसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर इस मुद्दे को बांग्लादेश के समक्ष उठाने का दबाव बनाया और फिर फरवरी 2015 में हसीना के साथ बैठक के दौरान पाबंदी हटाने की अपील की. आखिर सितंबर 2020 में हसीना सरकार ने सामयिक रूप से पाबंदी हटा ली थी.

अब दुर्गा पूजा से ठीक पहले इस पाबंदी से आम लोगों और कारोबारियों के चेहरे मुरझा गए हैं. पेट्रापोल में एक मछली आयातकर्ता विभूति मंडल कहते हैं, "यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है. हम हर साल त्योहार के सीजन में भारी मात्रा में इस मछली का आयात करते थे. अब हमें ओडिशा और म्यांमार की हिल्सा पर ही निर्भर रहना होगा."

कोलकाता फिश इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्य रंजन साहा कहते हैं, "हमें ओडिशा और म्यांमार से 30 फीसदी ज्यादा कीमत पर हिल्सा का आयात करना पड़ रहा है. बांग्लादेश से इस मछली के यहां नहीं आने की स्थिति में इसकी कीमत के आसमान छूने का अंदेशा है."

बंगाली परिवारों का हिल्सा प्रेम : मूल रूप से बंगालियों के लिए एक स्टेटस सिंबल का दर्जा हासिल कर चुकी इस मछली का पश्चिम बंगाल में सेवन देश की आजादी के बाद बढ़ा. इसकी वजह थे तत्कालीन पूर्वी बंगाल से यहां पहुंचने वाली बंगाली शरणार्थी.

बंगाली हिंदू परिवारों में हिल्सा के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता. वह चाहे शादी-विवाह का मौका हो या फिर किसी पूजा या त्योहार का. बाजारों में हिल्सा की आवक का मुद्दा स्थानीय मीडिया में अक्सर सुर्खियां बटोरता रहता है. इससे बंगाली जनजीवन और समाज में हिल्सा की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हिल्सा वैसे तो बंगाल की खाड़ी में भी पाई जाती है. लेकिन समुद्री हिल्सा उतनी स्वादिष्ट नहीं होती जितनी नदी वाली हिल्सा. यहां गंगा में भी हिल्सा मिलती है. लेकिन बांग्लादेश स्थित पद्मा नदी की हिल्सा का स्वाद खास माना जाता है. यह एक तैलीय मछली है. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. दूसरी मछलियों की तरह हिल्सा को काट कर नहीं बेचा जाता. लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी या छोटी मछली खरीद सकते हैं.

बांग्ला साहित्यकार मणि शंकर मुखर्जी बातचीत में कहते हैं, "हिल्सा बांग्ला समाज में एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है. लेकिन आसमान छूती कीमतों के कारण यह आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है. डेढ़ से दो किलो वजन वाली मछली सबसे बेहतर और स्वादिष्ट मानी जाती है. लेकिन इसकी कीमत 1,800 से दो हजार रुपए प्रति किलो तक हो सकती है."

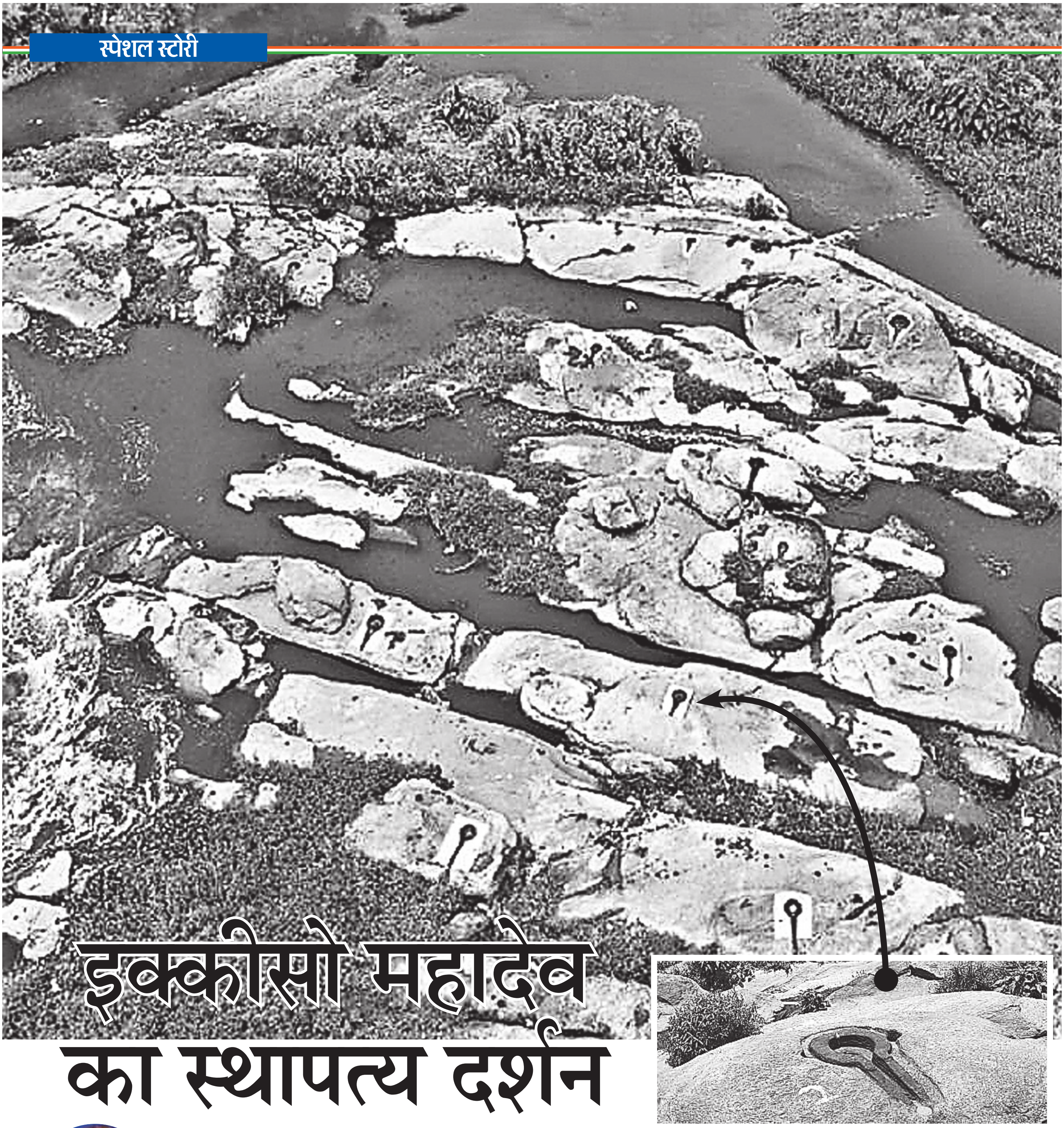

इक्कीसो महादेव का स्थापत्य दर्शन

▪ ब्रजभूषण पाठक

चुटिया छोटानागपुर की प्राचीन कालीन राजधानी रही है।

'चुटिया त्यजि कुसरा तिन्ह अभय, भीम कर्ण गढ़ तहा बनाय।'

अर्थात चुटिया राज्य को छोड़कर भीम कर्ण ने कुसरा अर्थात वर्तमान के खुखरा में अपने राज्य की राजधानी बनाई। जो वर्तमान के बेड़ो का ही खुखरा गांव है। महाराजा छोटानागपुर के भीम कर्ण, नागवंशियों में 29वें राजा थे जिनका राज्यारोहण वर्ष 1098 ई और शासन का अंतिम वर्ष 1132 ई है अर्थात उनका शासनकाल 34 वर्षों तक रहा।

स्वर्णवाहिनी स्वर्णरेखा और हरमू नदी के संगम स्थल पर उत्कीर्ण 21 शिवलिंगों के स्थापत्यकाल का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता तो भी यह बात प्रमाणित होता है कि इन शिवलिंगों का स्थापत्यकाल जो नागवंशीय राजाओं के द्वारा स्थापित करवाया गया यह या तो भीम कर्ण या उनके पूर्ववर्ती राजाओं में से किन्ही के द्वारा किया गया होगा अर्थात इन प्राचीन शिवलिंगों का स्थापत्यकाल 1132 ई से पूर्व का प्रतीत होता है, क्योंकि भीम कर्ण के शासनकाल का अंतिम वर्ष 1132 ई होता है और इसके पूर्व ही उन्होंने अपनी राजधानी खुखरा स्थानांतरित कर दी थी। ये 21 शिवलिंग जो दो नदियों के संगम स्थल पर उत्कीर्ण किए गए हैं बड़े ही प्रीतिकर प्रतीत होते हैं साथ ही साथ इस बात को अत्यंत स्पष्ट करते हैं कि इन दोनों नदियों का जल उस कालखंड में अत्यंत ही शुद्ध, प्रदूषणमुक्त रहा होगा, वरना भला कोई भी प्रदूषित जलधारा में शिवलिंगों की स्थापना क्यों करेगा या उत्कीर्ण क्यों करेगा।

झारखंड के इतिहास में चुटिया को एक अत्यंत ही

समृद्ध स्थान प्राप्त है। और ऐसा इसकी ऐतिहासिकता के कारण है। यह स्थान कभी छोटानागपुर की राजधानी हुआ करता था, उस समय इसका नाम चुटियानागपुर था। इस नामकरण की घटना का विवरण अत्यंत रोचक है।

ज्ञातव्य हो कि छोटानागपुर मुंडाओं की कर्मभूमि रहा है, मदरा मुंडा यहां के प्रथम शासक। इनकी प्रथम राजधानी सुतियाम्बे थी और बाद में फणि मुकुट राय को जब मदरा मुंडा ने अपनी व्यवस्था का कार्यभार सौंपा तो यह नागवंशियों की राजधानी बनी। मदरा मुंडा के वंशजों में से दो भाइयों के नाम चोट्टो और नागो था इन्हीं दोनों भाइयों के नाम पर इस स्थान का नाम चोट्टोनागपुर पड़ा और कालांतर से यह चुटियानागपुर और छोटानागपुर कहलाने लगा। सुतियाम्बे गढ़ से चुटियानागपुर नागवंशियों की राजधानी बनी और कालक्रम से राजा भीम कर्ण ने खुखरागढ़ को राजधानी बनाया। आज जहां जिस स्थान पर इक्कीसो महादेव स्थित है उस स्थान का चयन अत्यंत सोच समझकर किया गया प्रतीत होता है। इस स्थान पर हरमू नदी पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती आती है और उत्तरवाहिनी स्वर्णरेखा में समायोजित हो जाती है। जल का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर अत्यंत ही शुभ माना जाता है, यही कारण है कि विश्व में जहां कहीं भी शिवलिंग स्थापित हैं या श्यमंभू है सभी शिवलिंगों में जल का प्रवाह जलाभिषेक के समय उत्तर की ओर ही प्रवाहित होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन शिवलिंगों की स्थापना जिस संगम स्थल पर हुई है उसी के आसपास राजा का निवास स्थान भी रहा होगा, क्योंकि ठीक इसी स्थान के बगल में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका आजकल जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंदिर में स्थित शिवलिंग अति प्राचीन है ऐसा वहां के ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है, जो वहीं आसपास ही राजधानी के केंद्रबिंदु अर्थात राजा के महल होने का संकेत देता है।

चुटिया की प्रसिद्धि राम मंदिर को लेकर भी है जो कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाहदेव (शाही) जी के द्वारा निर्मित है जिसका उल्लेख मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर इस प्रकार लिखित है, "संवतकर युग सिंधु शशि अक्षय तृतीया चंद्र, ब्रह्मचारी हरिमठ दियो रघुनाथ नरेंद्र" (नरेंद्र से तात्पर्य यहां नाम से नहीं राजा से है) संवत 1742 अर्थात ई 1685 इस मंदिर का निर्माण इस बात को दर्शाता है कि भले ही राजधानी राजधानी राजा भीम कर्ण ने खुखरा में स्थानांतरित कर लिया हो चुटिया से नागवंशी राजाओं का लगाव बना रहा।

इक्कीसो महादेव स्थल के बारे में कुछ अन्य जानकारियां उल्लेखित हैंः स्वर्णरेखा नदी में स्वर्ण कणों के मिलने के कारण इस क्षेत्र के स्वर्णकारों के लिए यह नदी और इक्कीसो महादेव की खास महत्ता है। ऐसी किवदंती है, कि नागवंशी राजाओं पर जब मुगल शासकों ने आक्रमण किया तो नागवंशी रानी ने अपने स्वर्णाभूषणों को इस नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसके तेज धार से आभूषण स्वर्ण कणों में बदल गए और आज भी प्रवाहमान है। आज भी हर कार्तिक पूर्णिमा को संपूर्ण क्षेत्र के स्वर्णकार स्वर्णरेखा में डुबकी लगाते है और 21 शिवलिंगों का जलाभिषेक करते है।

16वीं शताब्दी में तत्कालीन नागवंशी राजा लालप्रताप राय के द्वारा संगम के चट्टानों में बनाए गए 21 शिवलिंगों के अवशेष एक सांस्कृतिक उन्नत समाज को दर्शाता है, जहाँ की जनजातीय समाज की शिव भक्ति आज भी उनकी परंपराओं में देखने को मिलती है। लेकिन आज ये प्राचीन धरोहर अपनी दुर्दशा के आँसू बहा रहा है,

सरकारी दस्तावेजों में शायद ही इस क्षेत्रा के संबंध में कोई आधिकारिक रिकार्ड हो, लेकिन परंपराओं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जानकारियां नागवंशी राज्य की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बयान करती है। यहीं कारण है, कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने पुरी की यात्रा के दौरान कई दिनों तक इस क्षेत्र में रहें। जिसके प्रमाण आज भी यहाँ के प्राचीन राम मंदिर में देखने को मिलते है।

नागवंशियों की राजधानी रहे इस क्षेत्र की भी अपनी महत्ता है, सात आम के बगीचों, 11 तालाब, 100 कुएं और दो नदियों के संगम का यह संपूर्ण क्षेत्र आज भी मौसम के व्यापक बदलाव से अछूता है। यहाँ के बुजुर्ग बताते है, कि इस क्षेत्र में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही पारिस्थतिकीय संतुलन की कल्पना की गई थी। खेती पर आश्रित रहने वाला यह क्षेत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ रहा, बल्कि नैतिक मूल्यों को भी स्वयं में समाहित किए रहा। सेवानिवृत स्कूल हेडमास्टर शिवशंकर सिंह के अनुसार 1947 से पूर्व आजतक चुटिया के लोगों ने हथकड़ी नहीं देखी थी, अंग्रेज अफसर भी इस इलाके से अगर किसी अपराधी को लेकर गुजरते थे, तो नागवंशियों की राजधानी में हथकड़ी खोल दी जाती थी, वे भी मानते थे, कि इक्कीसों महादेव के इस क्षेत्र में कोई अपराधी भी भाग नहीं सकता। लोग आजादी के पूर्व अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे।

ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें तो वर्तमान झारखण्ड राज्य का छोटानागपुर क्षेत्र नागवंशी राजाओं के समय चुटियानागपुर के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी तत्कालीन रांची शहर के रेलवे स्टेशन का क्षेत्र रहा था। आज के रेलवे स्टेशन से महज पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वर्णरेखा नदी और हरमू नदी के संगम में "दहराटांड" अर्थात राजा का किला स्थित था। नागवंशी राजाओं ने अपने महल के करीब 21 चट्टानों में शिवलिंग का निर्माण कराया। राजपरिवार की दिनचर्या इन 21 शिवलिंगों में जलाभिषेक के साथ ही शुरू होती थी। राजा के महल के निकट केवल दो आदिवासी परिवार ही रहते थे, इसलिए इस इलाके को दुघरवा कहा जाता था। राजा के अलावे केवल इन्हीं दो परिवारों को ही इस इलाके में रहने की अनुमति थी, शेष ग्रामवासी दहराटांड से दूर रहते थे। चट्टानों में स्थित शिवलिंग की महत्ता के संबंध में आज भी किवदंती प्रचलित है, कि दो चट्टानों के बीच एक संकरा दर्रा था और राजा किसी भी फैसले को इसी कसौटी पर तौलता था। कोई भी चोरी अथवा झूठ बोलने के आरोप में राजा के पास लाया जाता था, निर्दोष व्यक्ति कितना भी मोटा क्यों न हो वह उस संकरे दर्रे से आसानी से निकल जाता था, लेकिन दोषी कितना भी पतला क्यों न हो, वह उस दर्रे को पार नहीं कर पाता था। जातीयता और ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से राजा ने प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा में इक्कीसो महादेव मठ (अब मंदिर) में स्वर्णरेखा नदी के तट पर, दरिद्रनारायण भोजन कराने की शुरुआत की थी, जो आज भी उसी रूप में आयोजित की जाती है। समाज के प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आज भी दरिद्रनारायण भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग इक्कीसो महादेव को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण करते है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के क्रम में वे इस क्षेत्र से गुजरे थे और वे नाग राजाओं से मिले थे, नाग राजा उस समय गंधर्वों के आक्रमण से काफी परेशान थे, तब नाग राजाओं ने अर्जुन के समक्ष अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगायी थी, अर्जुन ने गंधर्वों को परास्त कर नागवंशियों के साम्राज्य की रक्षा की थी। नाग राजाओं के निवेदन से ही नाग राजकुमारी का विवाह अर्जुन से संपन्न हुआ, जिससे बबलुवाहन की उत्पत्ति हुई, जिसकी चर्चा महाभारत के प्रसंगों में मिलती है। ये नागवंशी राजा शिव के उपासक थे और ये जहाँ भी अपने साम्राज्य का प्रसार किया वहाँ वे नदियों के किनारे शिव मठों की स्थापना करते चले गए, आज भी इक्कीसो महादेव के अलावे घघारी महादेव और आम्रेश्वर धाम जैसे कई प्राचीन शिव मठ (अब मंदिरों के रूप में) देखने को मिलते है।

लेकिन बिहार से अलग होकर झारखण्ड बनने के बाद ऐसे प्राचीन धरोहरों के प्रति सरकार भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। राज्य निर्माण के 16 वर्षों के बाद भी आजतक ऐसे धरोहरों को चिह्नित तक नहीं किया जा सका, इसे राज्य कर दुर्भाग्य ही कहे, कि आजतक राज्य का कोई आधिकारिक इतिहास नहीं है और न ही कोई ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन। अगर सरकार चाहे तो इक्कीसो महादेव जैसे महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर को संरक्षित कर धार्मिक पर्यटन का विकास किया जा सकता है।

वर्तमान विश्व राजनीति और भारत की भूमिका

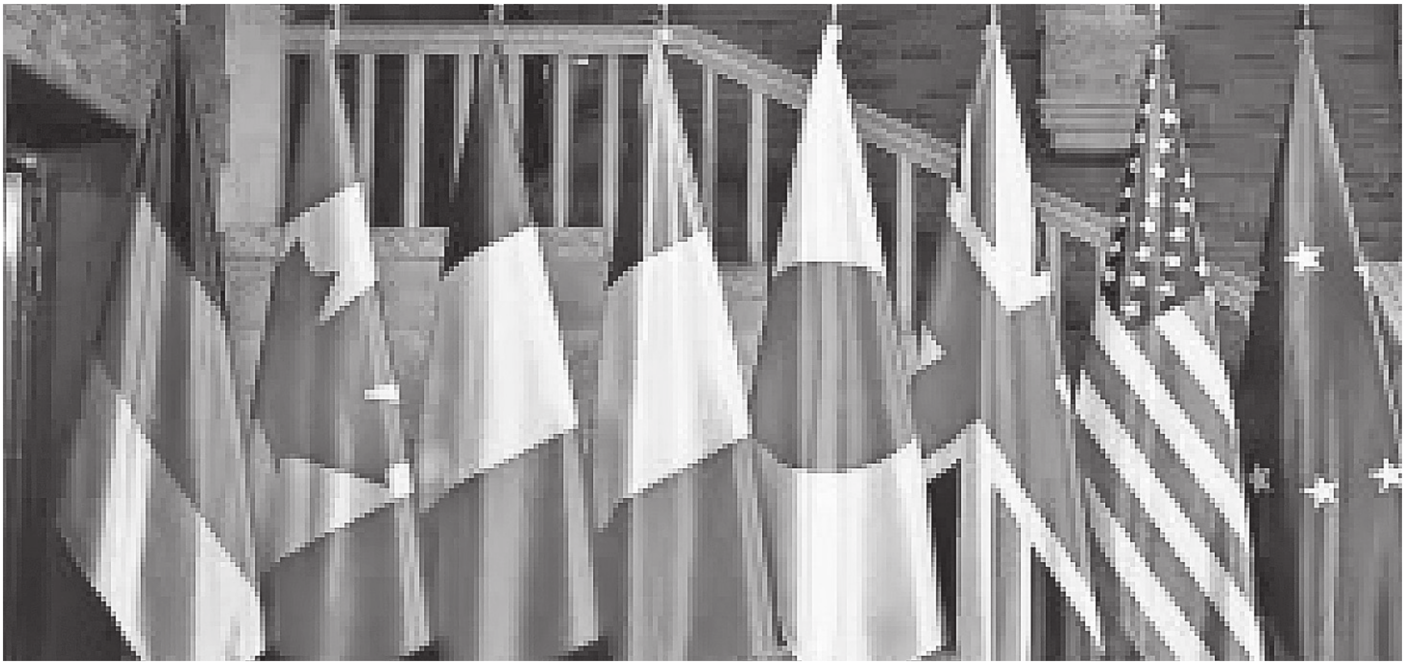

वर्तमान में विश्व राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ अनेक चुनौतियाँ और अवसर एक साथ सामने आ रहे हैं। शीत युद्ध के अंत के बाद वैश्विक शक्ति-संतुलन में तेजी से परिवर्तन हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब सबसे बड़ी भू-राजनीतिक धुरी बन गई है। वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय विवादों पर अब नई दिशा में बहस हो रही है। ऐसे में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। **अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा** : अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक, सैन्य और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव पैदा किया है। चीन अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत दोनों देशों के बीच एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने अपनी 'गुट-निरपेक्ष' नीति से आगे बढ़ते हुए अब बहुपक्षीय कूटनीति अपनाई है। वह एक ओर अमेरिका के साथ सामरिक और आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन के साथ अपने पुराने संबंधों को भी संतुलित कर रहा है। क्वाड (Quad) जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि वह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर से ध्रुवीकृत कर दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। यूरोप के लिए यह युद्ध एक ऊर्जा संकट के रूप में उभरकर आया है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा रूस पर निर्भर है। भारत ने इस संकट के दौरान अपनी स्थिति को सावधानी से संभाला है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी, जबकि पश्चिमी देशों के साथ भी संतुलन बनाए रखा। यह भारत की 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' को दर्शाता है, जहाँ वह किसी एक खेमे का समर्थन करने के बजाय अपने हितों के आधार पर निर्णय लेता है। **उभरते क्षेत्रीय विवाद और भारत की भूमिका** : भारत न केवल वैश्विक राजनीति में, बल्कि दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दक्षिण एशिया में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव भी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके अलावा, भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। सार्क (SAARC) और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत की भूमिका इसे एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है। जलवायु परिवर्तन और भारत की प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन वैश्विक राजनीति का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ भारत की भूमिका निर्णायक है। भारत ने COP26 में 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जबकि पश्चिमी देश अधिक जल्दी नेट-जीरो का लक्ष्य चाहते हैं, भारत का दृष्टिकोण यह है कि विकासशील देशों को अपनी विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय दिया जाना चाहिए। भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लेकिन जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर अभी भी विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

निष्कर्ष : वर्तमान वैश्विक राजनीति में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वह अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा हो, रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट हो या जलवायु परिवर्तन की चुनौती—हर जगह भारत की स्थिति निर्णायक और संतुलनकारी है। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज को लगातार मजबूत कर रहा है। यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत का प्रभाव वैश्विक राजनीति में और भी बढ़ेगा, और उसे एक जिम्मेदार, सक्षम और निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जाएगा। भारत को अपनी कूटनीतिक कौशल, आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति के साथ इस नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका को और भी सुदृढ़ करना होगा।

गौतम अदाणी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी को पछाड़ा

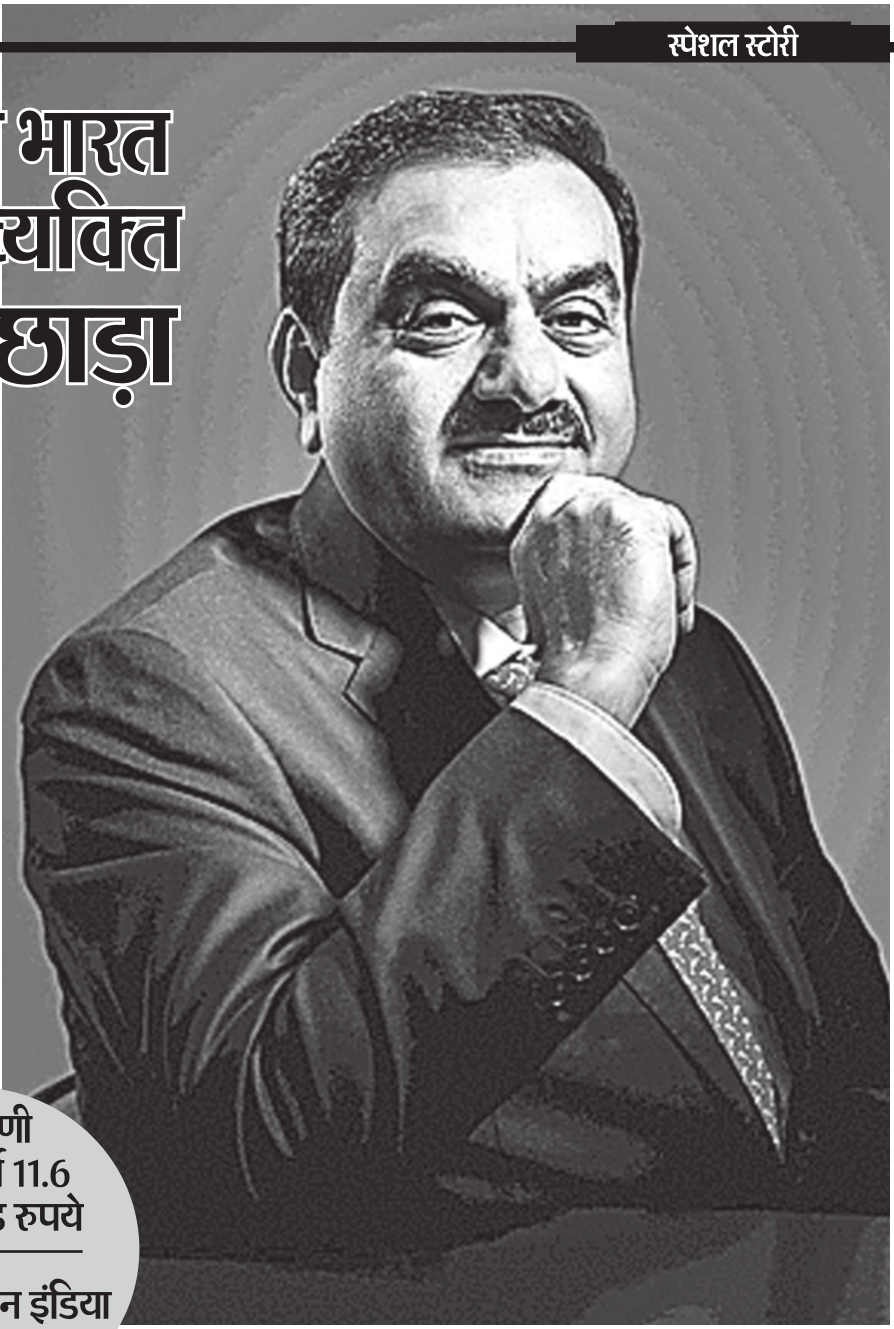

हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण हुए नुकसान की भरपाई करते हुए, गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले साल 95% बढ़कर 11.6 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिससे उन्हें मुकेश अंबानी की जगह सबसे अमीर भारतीय बनने में मदद मिली। 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंबानी की कुल नेटवर्थ 25% बढ़कर 10.14 लाख करोड़ रुपये हो गई।

2023 की रिपोर्ट में अदाणी की संपत्ति 57% घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपये रह गई और अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ काफी आगे रहे.

अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए कई आरोपों के बाद अदाणी की नेटवर्थ में तेजी से गिरावट आई है लेकिन समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है। 2014 के एडिशन में, हुरुन ने अदाणी की संपत्ति 44,000 करोड़ रुपये आंकी थी, जिसने उन्हें तब, दसवां सबसे अमीर भारतीय बना दिया था।

एचसीएल के शिव नाडर और उनका परिवार 2024 में 3.14 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ एक स्थान के फायदे के साथ तीसरे सबसे अमीर बन गए, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला 2.89 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ एक पायदान नीचे चौथे स्थान पर खिसक गए।

» अदाणी की नेटवर्थ 11.6 लाख करोड़ रुपये

» 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट का दावा

सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी ने 2.50 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ पिछले साल छठे स्थान के मुकाबले पांचवां सबसे अमीर का टैग हासिल करते हुए लिस्ट में अपनी बढ़त जारी रखी।

स्व-निर्मित महिलाओं में ज़ोहो की राधा वेम्बू 47,500 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे धनी थीं, जबकि ज़ेप्टो के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा और आदित पालीचा, जो लगभग 20 वर्ष के हैं, 3,600 रुपये और 4,300 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ लिस्ट में सबसे कम उम्र के थे।

लिस्ट, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले भारतीयों को शामिल किया गया है। 2024 में ये संख्या 1,539 हो गई है इसमें 220 व्यक्ति नए भी जुड़ गए है। साल में संचयी संपत्ति में 46% की वृद्धि देखी गई है। अभिनेता शाहरुख खान ने 7,300 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ लिस्ट में अपनी शुरुआत की, जो उनकी बिजनेस पार्टनर जूही चावला की तुलना में बहुत अधिक थी, जिनकी 4,600 करोड़ रुपये की नेटवर्थ ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दूसरा स्थान हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि 16 पेशेवरों ने भी लिस्ट में जगह बनाई है, अरिस्टा नेटवर्क्स की मुख्य कार्यकारी जयश्री उल्लाल 32,100 करोड़ रुपये के साथ सबसे अमीर हैं और डी-मार्ट के मुख्य कार्यकारी इग्नाटियस नाविल नोरोन्हा 6,900 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट के मुताबिक में कहा गया है कि गेरा डेवलपमेंट्स के कुमार प्रीतमदास गेरा की संपत्ति 2024 की सूची में सबसे तेजी से 566% बढ़ी, जबकि अंबानी और अदाणी की संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ी वृद्धि हुई।

एपीएसईज़ेड गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ विकसित करेंगेः अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड) ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ नंबर 13 को विकसित करने के लिए डीपीए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एपीएसईज़ेड ने इसके तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, डीपीए कंटेनर और क्लीन कार्गो टर्मिनल लिमिटेड (डीपीएसीसीटीएल) का गठन किया है, जो बर्थ पर संचालन करेगी।

जुलाई 2024 में, एपीएसईज़ेड को 30 साल की रियायती अवधि के लिए बर्थ के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए एलओआई प्राप्त हुआ था। एपीएसईज़ेड कंटेनर कार्गो सहित बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो के लिए डीबीएफओटी (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण) मॉडल के तहत बर्थ विकसित करेगा।

बर्थ नंबर 13 की लम्बाई 300 मीटर है और यह सालाना 5.7 एमएमटी क्षमता प्रदान करता है। इसके वित्तीय वर्ष 2027 में चालू होने की संभावना है।

एपीएसईज़ेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा,"बर्थ नंबर 13 दीनदयाल पोर्ट पर हमारी उपस्थिति को दर्शाएगा। अब हम बंदरगाह पर सूखे बल्क कार्गो के अलावा बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो को संभालेंगे। यह स्थान पश्चिमी तट पर हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा और गुजरात और उत्तर भारत में ग्राहकों को सेवा देने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। "

क्यों जरूरी है जनगणना

जनगणना सूचना का एक अहम स्रोत है। इसके जरिए देश के लोगों के बारे में कई तरह की सांख्यिकीय जानकारी हासिल होती हैं। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों, योजनाओं के निर्माण के अलावा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन में किया जाता है।

संसद, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है।

देश में मौजूद बिजनेस सेक्टर और उद्योग भी इन्हीं आंकड़ों के जरिए अपनी पहुंच को बेहतर बनाते हैं। साथ ही वित्त आयोग द्वारा राज्यों को मिलने वाला अनुदान भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है।

जनगणना होनी क्यों जरूरी है इसका उदाहरण देते हुए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विकास कुमार कहते हैं, "कोरोना काल के दौरान जिस तेजी से भारत के कई प्रदेशों से लोगों का प्रवास हुआ, अगर समय रहते हमारे पास उसके बेहतर आंकड़े होते कि किस जिले या प्रदेश से कितनी संख्या में और कितनी अवधि के लिए लोग बाहर गए हैं तो स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन को बेहतर मदद मिलती।"

पापुलेशन स्टडीज में पीएचडी कर चुके अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉ। उदय शंकर मिश्र बताते हैं, "हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें माहिर हैं लेकिन किसके लिए करना चाहते हैं ये हमें पता नहीं है। सरकार कहती है कि हम इतने लोगों को घर दे देंगे लेकिन जब हमारे पास आंकड़े ही नहीं हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोगों को घरों की जरूरत है तो पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं होगा।"

भारत में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजनाओं का हाल अच्छा नहीं है। बुजुर्गों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 2021-2030 रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60 साल से ज्यादा की उम्र के चालीस प्रतिशत बुजुर्ग वित्तीय सुरक्षा के मामले में बहुत खराब हाल में हैं और लगभग हर पांचवें बुजुर्ग के पास आय का कोई साधन नहीं है।

पिछले दशक से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। प्रोफेसर मिश्र ने बताया, "शहरी क्षेत्र का मतलब है ऐसा इलाका जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होता है और लोग वहां रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे आंकड़े ही नहीं है कि हम ऐसे नए पैदा हुए शहरी क्षेत्रों की पहचान कर सकें और वहां के लोगों के लिए बेहतर योजनाएं बना सकें।"

समय पर 'जनगणना' क्यों जरूरी

▪ आयुष यादव

देश में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड महामारी की वजह से टाल दी गई लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी इस पर स्थिति अभी साफ नहीं है।

145 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन ये आंकड़े भारत सरकार ने नहीं जारी किए थे बल्कि दूसरी संस्थाओं ने किए। कारण ये कि हर दस साल पर कराई जाने वाली जनगणना 13 साल से कराई ही नहीं गयी है।

जनगणना के मायने क्या हैं : प्राचीन रोमन साम्राज्य में सदियों पहले जनगणना के प्रमाण पाए गए थे। जबकि आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके सबसे पहली जनगणना सन 1749 में स्वीडन में कराई गई थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1872 में पहली अनियमित और 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। तब से लगातार हर दस साल पर भारत में जनगणना होती रही है।

जनगणना का मतलब है किसी देश में निवास करने वाले सभी लोगों के एक विशेष समयावधि में अलग-अलग मानकों के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका विश्लेषण करने के बाद उन्हें जारी करना। जनगणना के जरिए जो आंकड़े मिलते हैं उनका इस्तेमाल बजट आवंटन, नीति निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण जैसी जरूरी चीजों में किया जाता है।

पहली बार जनगणना में इतनी देरी : भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर दशक में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हालांकि 2021 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी थीं लेकिन 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में भी कोविड महामारी की बात कहते हुए जनगणना न कराए जाने की जानकारी दी थी।

शिक्षाविद विजेंदर चौहान कहते हैं, "विपक्षी पार्टियों द्वारा जातिगत जनगणना का लगातार मुद्दा उठाना और केंद्र सरकार के घटक दलों का इस पर मुखर होना कहीं न कहीं इस देरी का कारण जरूर है।" उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां जनगणना करवा पाना आसान काम नहीं रहा है और मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान से तुलना करते हुए कई बार इस बात का श्रेय लिया है कि हम इस मामले में उनसे कहीं बेहतर हैं लेकिन अब जनगणना हमारे यहां भी एक राजनीतिक औजार बन चुकी है।

सर्वे नहीं हो सकता जनगणना का विकल्प : देश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल नई नीतियों को तैयार करने और पिछली नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

अपनी किताब 'नंबर्स इन इंडियाज पेरिफेरीः दि

पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स' का हवाला देते हुए प्रोफेसर विकास कुमार कहते हैं, "सैंपलिंग फ्रेम और वास्तविक आंकड़े में कई बार बहुत फर्क दिखाई देता है। गरीबी की दर और गरीबी रेखा जैसे मानक इनकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं और इसका सीधा असर पब्लिक पॉलिसी पर पड़ता है।"

वो बताते हैं कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की गई गलती की वजह से वित्त आयोग द्वारा नागालैंड को लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित हो गया था और जम्मू कश्मीर के मामले में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन में गलतियां देखने को मिली थीं। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है।

सर्वे और जनगणना के आंकड़ों की तुलना करते हुए डॉ। विजेंदर चौहान कहते हैं, "सर्वे के डेटा पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वे के डेटा को सरकार अपनी मर्जी से जैसा दिखाना चाहे उसे वैसा प्रदर्शित कर सकती है लेकिन जनगणना के साथ ऐसा करना संभव नहीं है।" वे आगे कहते हैं कि बतौर शिक्षाविद पिछले दस सालों में सरकार से भरोसेमंद डाटा जुटा पाना जटिल काम बन चुका है।

कब तक इस्तेमाल हो सकते हैं आंकड़े : प्रोफेसर विकास कुमार बताते हैं कि हर जनगणना के बाद अगले 25 साल का अनुमान लगा लिया जाता है। इसलिए जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 2036 तक का अनुमान सरकार के पास था लेकिन सिर्फ अनुमान की बदौलत नीतियां तैयार करने से गड़बड़ हो सकती है।

प्रोफेसर उदय शंकर कहते हैं, "दशकीय जनगणना का डेटा कभी पुराना नहीं होता। यह हमारे लिए कई सालों तक

1।4 अरब आबादी वाले देश में जनगणना सही समय पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीति निर्माता सारी योजना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही बना रहे हैं

चेकप्वाइंट के रूप में काम आता है। लेकिन जब हम एक दशक आगे बढ़ जाते हैं तो पुरानी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल चेक प्वाइंट की तरह नहीं किया जा सकता क्योंकि काफी चीजें बदल चुकी होती हैं इसलिए जनगणना में देरी कई समस्याएं खड़ी कर सकती है।"

जब सरकार अलग-अलग तबकों जैसे - बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किशोरों आदि के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है तो इनका लक्ष्य इन तक समुचित लाभ पहुंचना होता है लेकिन सही आंकड़े के अभाव में न तो ये कार्यक्रम सफल हो सकते हैं और न ही नए कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।

जनगणना कराए जाने की जरूरत पर बल देते हुए डॉ। विजेंदर कहते हैं, "तमाम अंतरराष्ट्रीय निकायों के आंकड़ों के साथ जब भी भारत के आंकड़ों की बात की जाती है तो उसके साथ ये चेतावनी लिखी हुई दिखाई देती है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं या फिर पुराने हो चुके हैं।"

सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना की प्रक्रिया : सरकार सितंबर महीने से जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जनगणना के इस सर्वे में लगभग 18 महीने लगेंगे और नतीजे मार्च 2026 में आने की उम्मीद है।

सर्वेक्षण को पूरा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। सरकार के भीतर और बाहर के अर्थशास्त्रियों ने ताजा जनगणना में देरी की आलोचना की है क्योंकि इससे आर्थिक डाटा, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमान समेत कई अन्य सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

1।4 अरब आबादी वाले देश में जनगणना सही समय पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीति निर्माता सारी योजना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही बना रहे हैं। सरकार जो भी योजना बनाती है या कार्यक्रम शुरू करती है उसका आवंटन जनगणना के आधार पर होता है।

वर्तमान में इनमें से अधिकांश डाटा सेट और उनके परिणामों पर आधारित सरकारी योजनाएं 2011 में जारी अंतिम जनसंख्या जनगणना पर आधारित हैं। जिसके कारण कई सरकारी योजनाएं और नीतियां कम प्रभावी हो गईं हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जनगणना कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गृह मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक समय सीमा तैयार की है और उनका लक्ष्य मार्च 2026 तक नतीजे जारी करना है, जिसमें 15 साल की अवधि शामिल है।

2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया था।

सरकार खुदरा महंगाई दर समेत अपने आर्थिक आंकड़ों में भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य सहित विभिन्न श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है।

जनगणना जैसी गहन जनसांख्यिकी कवायद बेहद जरूरी है। भारत जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। उदाहरण के लिए यह आबादी के आकार जैसी बुनियादी जानकारी मुहैया कराता है।

पेरिस पैरालंपिक में अपने सबसे सफल प्रदर्शन से भारत ने लिखी स्वर्ण कहानी

7 गोल्ड सहित जीते 29, ओलंपिक के मुकाबले 6 गुणा से बस एक कम - दिखाया दम

▪ चंचल भट्टाचार्य

2024 के पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय रणबांकुरों ने मिलकर एक रजत और 5 कास्य जीते. जबकि पेरिस पैरालिंपिक में हमारे 84 जाँबाजों (एथलीट्स) ने केवल 7 स्वर्ण ही नहीं बल्कि 9 रजत और 13 कास्य सहित कुल 29 मेडल जीते. यह आँकड़ा अपने आपमें हमारी कहानी, हमारी उपलब्धि और हमारे भविष्य को भी दिखाने के लिये पर्याप्त है. यह उपलब्धि टोक्यो पैरालिंपिक 2020 के 5 स्वर्ण सहित 19 पदकों से कहीं आगे है. इस रिकॉर्ड प्रदर्शन का मतलब यह भी है कि भारत ने अपने पैरालिंपिक इतिहास में 50 पदकों का आँकड़ा पार कर लिया है.

फ्रांस के पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितम्बर तक आयोजित पैरालिंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा-एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. भारत ने 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा की जो टोक्यो 2020 की तुलना में तीन अधिक है. भारतीय पैरा-एथलीटों ने पेरिस 2024 में तीन नये खेलों में भाग लिया- पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो.

उपलब्धियों की फेहरिस्त काफी लम्बी है. अवनि लेखरा पैरालिंपिक खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गयीं जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच 1 निशानेबाजी स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपना खिताब बरकरार रखा.

भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार पहला स्थान प्राप्त किया. धरमबीर ने क्लब थ्रो एफ 51 स्पर्धा में 34.92 मीटर के नये एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता जबकि परनव सूरमा ने इसी स्पर्धा में सिल्वर जीता. प्रवीण कुमार ने भी ऊंची कूद टी 64 का खिताब जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया और भारत को छठा स्वर्ण दिलाया.

भाला फेंक के दिग्गज सुमित अंतिल ने भी पैरालिंपिक में अपना खिताब बचाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक एफ 64 स्पर्धा में 70.59 मीटर की शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता जो पैरालिंपिक का नया रिकॉर्ड है. यहाँ यह बताना जरूरी है कि सुमित ने टोक्यो 2020 पैरालिंपिक में बनाये गये अपने पिछले रिकॉर्ड को न केवल एक बार बल्कि प्रतियोगिता के दौरान तीन बार तोड़ा. उधर हाई जंप टी 42 वर्ग में कांस्य पदक जीतने के साथ, मरियप्पन थंगावेलु लगातार तीन पैरालिंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गये. उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण पदक और टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था. प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर टी 35 रेस में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता. यह पैरालिंपिक में ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था. 200 मीटर में उनके कांस्य ने उन्हें खेलों में भारत की सबसे सफल एथलीट बना दिया, क्योंकि वह दो पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी. कुल मिलाकर, भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में चार पदक जीते. इसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थीं जो महिलाओं की 400 मीटर टी 20 श्रेणी में कांस्य पदक के साथ पैरालिंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से विकलांग भारतीय एथलीट बनीं.

तीरंदाजी में भी रिकॉर्ड बनाये गये. बिना बांह की तीरंदाज शीतल देवी ने रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिये विश्व रिकॉर्ड बनाया लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहीं. लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन इवेंट में

भारत के पदक विजेताओं की सूची में

- अवनि लेखरा — (शूटिंग महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच 1 स्वर्ण),
  मोना अग्रवाल (शूटिंग महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग कास्य)
- प्रीति पाल — (महिलाओं की 100 मीटर टी 35 कास्य),
- मनीष नरवाल — (शूटिंग पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच 1 रजत),
- रुबीना फ्रांसिस — (शूटिंग महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच 1 कास्य),
- प्रीति पाल — (महिलाओं की 200 मीटर टी 35 कास्य),
- निषाद कुमार — (पुरुषों की ऊंची कूद टी 47 रजत),
- योगेश कथुनिया — (पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ 56 रजत),
- नितेश कुमार — (बैडमिंटन पुरुष एकल एसएल 3 सोना),
- तुलसीमति मुरुगेसन — (बैडमिंटन महिला एकल एसयू 5 रजत) शामिल हैं.
  इसके साथ ही मनीषा रामदास (बैडमिंटन महिला एकल एसयू 5 कास्य)
- सुहास यतिराज — (बैडमिंटन पुरुष एकल एसएल 4 रजत)
- राकेश कुमार एवं शीतल देवी — (तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन कास्य)
- सुमित अंतिल — (भाला फेंक एफ 64 स्वर्ण)
- नित्या श्री सिवान — (बैडमिंटन महिला एकल एसएच 6 कास्य)
- दीप्ति जीवनजी — (महिलाओं की 400 मीटर टी 20 कास्य)
- मरियप्पन थंगावेलु — (पुरुषों की ऊंची कूद टी 63 कास्य)
- शरद कुमार — (पुरुषों की ऊंची कूद टी 63 रजत)
- अजीत सिंह — (पुरुषों की भाला फेंक एफ 46 रजत)
- सुन्दर सिंह गुर्जर — (पुरुषों की भाला फेंक एफ 46 कास्य)
- सचिन खिलारी — (पुरुषों की शॉटपुट एफ 46 रजत)
- हरविंदर सिंह — (तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्वर्ण)
- धरमबीर — (पुरुषों का क्लब थ्रो एफ 51 स्वर्ण) ने भी भारत के लिये जीत दर्ज की और अपने हिस्से का मेडल पक्का किया.
- परनव सूरमा — (पुरुषों का क्लब थ्रो एफ 51 रजत)
- कपिल परमार — (जूडो पुरुष 60 किग्रा जे 1 कास्य)
- प्रवीण कुमार — (पुरुषों की ऊंची कूद टी 64 स्वर्ण)
- होकाटो होतोझे — (पुरुषों की शॉटपुट एफ 57 कास्य)
- सिमरन — (महिलाओं की 200 मीटर टी 12 कास्य)
- नवदीप सिंह — (पुरुषों की भाला फेंक एफ 41 स्वर्ण) ने भी अपने और अपने राष्ट्र के लिये इतिहास लिखा.

कुल मिलाकर तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 रजत सहित 2, एथलीट में 4 स्वर्ण 6 रजत व 7 कास्य सहित कुल 17, बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 रजत व 2 कास्य सहित कुल 5 पदक हमारे हिस्से आये. जूडो में 1 कास्य, शूटिंग में 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कास्य सहित कुल 4 पदक मिले अर्थात कुल मिलाकर 7 स्वर्ण 9 रजत एवं 13 कास्य सहित कुल 29 मेडल.

विश्व रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया महज 17 साल की उम्र में शीतल ने भारत की सबसे कम उम्र की पैरालिंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया क्योंकि उन्होंने राकेश के साथ मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता. बाद के समय में, भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन भी यहीं मिला.

भारतीय पैरालिंपिक समिति के अध्यक्ष और दो पैरालिंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा-एथलीट देवेन्द्र झाझरिया ने पेरिस पैरालिंपिक शुरू होने से एक दिन पहले 27 अगस्त को कहा था कि भारत, इतिहास रचने जा रहा है और उनकी बात पूरी तरह सच साबित हुई. उन्होंने भारत के कम-से-कम 25 पदक जीतने की बात कह लोगों को चौकाया था. टोक्यो में यह संख्या 19 थी और किसी को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ. पर दस दिन बाद ही भारत ने रिकॉर्ड 29 पदकों के साथ अपने पैरालिंपिक अभियान को समाप्त किया यह 1968 में पैरालिंपिक में अपनी शुरुआत के बाद से सभी खेलों में भारत द्वारा जीते गए 30 पदकों से एक पदक कम है. इस सफलता की गहराई और गंभीरता को समझने के लिये अतीत में झाँकना होगा. दो दशक पहले झाझरिया के पैरालिंपिक डेब्यू में खुद ही पैसे खर्च किये और जब वे एथेंस पैरालिंपिक से स्वर्ण पदक जीतकर लौटे तो किसी ने उन्हें एक माला तक नहीं पहनाया. जबकि आज भारत के पैरा-एथलीट ढोल और मालाओं के साथ वापस आये और उनपर पैसों अर्थात भारी पुरस्कार राशि की बारिश हो रही है. बेहतर संरचना और सुविधायें, नये प्रशिक्षक एवं मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग का यह सीधा फायदा है जो अब ज़मीन पर नज़र आ रहा है और परफॉरमेंस में भी. बदलाव की बात करें तो एक प्रमुख उत्प्रेरक 2016 का रियो पैरालिंपिक था जहाँ चार पदक के साथ भारत ने 32 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और पैरा-एथलीटों ने 2016 ओलंपिक में अपने सक्षम साथियों की तुलना में दो पदक अधिक जीते. तबतक इन्हे बहुत हद तक नज़रअंदाज़ ही किया जाता था. झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक और वरुण भाटी इसी दौरान घर-घर में मशहूर हो गये. इनकी कहानियों ने कई लोगों को प्रेरित किया. तब पहली बार झाझरिया को केंद्र और राज्य सरकारों से 1 करोड़ रूपये से अधिक मिले और उन्हें ज़मीन दी गयी. मलिक को हरियाणा सरकार से 4 करोड़ रूपये मिले. उनके उदाहरणों ने सभी को प्रेरणा दी. तबतक जो लोग सोचते थे कि पैरा स्पोर्ट्स में कोई भविष्य नहीं है, उन्हें अब एक उद्देश्य दिखाई दिया. वैसे खिलाड़ियों के पास भी पहचान, नकद पुरस्कार और बेहतर जीवन का मौका है. केवल एक उदाहरण. नित्या श्री सिवन की ने 11 साल की उम्र में 2016 पैरालिंपिक को टीवी पर देखा और महसूस किया कि उनका पैरा-बैडमिंटन में भविष्य हो सकता है और 2024 में उन्होंने पेरिस पैरालिंपिक (महिला एकल एसएच 6) में कांस्य पदक जीता है. यह बहुतों की प्रेरणा का भी परिणाम है.

निषाद कुमार का उदाहरण ले. साढ़े सात साल की उम्र में खेत में काम करते समय हाई जम्पर ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था. बड़े होने पर आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा. एक समय ऐसा था जब उनके परिवार के पास ज़रूरी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. सरकार ने पैरा-एथलीटों को उनके सक्षम समकक्षों के बराबर नकद ही पुरस्कार दिये हैं (स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 75 लाख, रजत पदक विजेताओं के लिए 50 लाख और कांस्य विजेताओं के लिए 30 लाख रूपये जबकि मिश्रित टीम पदक विजेताओं के लिए 22.5 लाख. सुविधाओं के मामले में पेरिस पैरालिंपिक के लिये 74 करोड़ रूपये खर्च का अनुमान किया गया जो टोक्यो के लिये किये खर्च का दोगुना है. लेकिन सही अर्थो में कहा जाये तो भारत के पैरा-एथलीटों को सिर्फ़ जीत के समय ही नहीं, बल्कि हर समय समर्थन की ज़रूरत है.

कांस्य पदक जीतने के बाद एक एथलीट ने अपना पदक, अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए कहा कि वह अक्सर भूखी रहती थी ताकि मैं खाना खा सकूँ और प्रशिक्षण जारी रख सकूँ क्योंकि हमारे पास एक दिन में दो समय का खाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे. झाझरिया के अनुसार प्रायोजनों को अलग रखते हुए स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है. शुरुआत के लिये पैरा-स्पोर्ट्स को अधिक लोकप्रिय बनाना और एथलीटों के लिए स्टेडियमों को सुलभ बनाने को अपना लक्ष्य बताते हुए देश भर के 600 जिलों में सुलभ खेल स्टेडियम बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि जमीनी स्तर तक पहुंच बनाई जा सके. स्टेडियमों में रैंप, व्हीलचेयर के माध्यम से सुलभ हों और सुलभ शौचालय भी पैरा-स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिये कुछ बुनियादी जरूरते हैं. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2024 के पेरिस पैरालिंपिक ने न केवल धारणा बदली है बल्कि जिस प्रकार का प्रदर्शन पेरिस पैरालिंपिक में हमारे सितारों ने किया है और स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक बटोरे हैं वह भविष्य के प्रति भरोसा जगाता है. भारत के पैरा-एथलीटों ने दिखा दिया है कि उनके आसमानी उत्साह की कोई सीमा नहीं है. यदि सरकार और कॉरपोरेट से समर्थन और मदद मिले तो भारत वैश्विक पैरा-स्पोर्ट्स में सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बन सकता है. यह संकल्प भी है, प्रतिज्ञा भी और अब देश के करोड़ो लोगों का भरोसा भी.

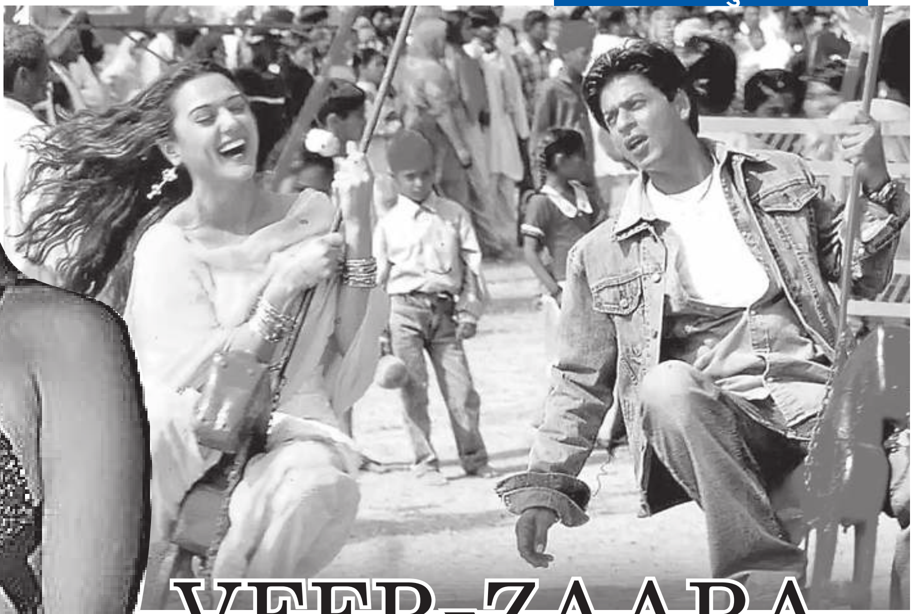

VEER-ZAARA ने मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री

सिनेमाघरों में एक बार फिर पुरानी फिल्में रिलीज हुई है, जिनमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की पॉपुलर फिल्म 'वीर-जारा' का नाम भी शामिल है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाका कर दिया है, फिल्म ने अपने नाम नया रिकॉर्ड बना डाला है। 'वीर-जारा' में किंग खान और प्रीति जिंटा की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था और एक बार फिर इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को थियेटर तक खींच ले आई है।

'वीर-जारा' ने पहली बार साल 2004 में थियेटर में दस्तक दी थी और तब से लेकर 2024 तक फिल्म को कई बार थियेटर में रि-रिलीज किया गया है। दुनियाभर में किंग खान की फिल्म 'वीर-जारा' रिलीज हुई है और मूवी ने अब तक वर्ल्डवाइड टोटल 102.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन (Veer Zaara Re-Release Collection) कर लिया है। तरण आदर्श ने एक ट्वीट कर यह खुशखबरी साझा की है और अपने ट्वीट में उन्होंने फिल्म के कलेक्श के बारे में भी बताया है।

युध्रा में साथ में आये सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल

गली बॉय बनकर बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एक बार फिर सिनेमाघर में अपनी नई फिल्म 'युध्रा' के साथ आ गए हैं। 'युध्रा' में उनके साथ साउथ की बोल्ड एक्ट्रेस मालविका मोहनन और डांस और एक्टर राघव जुयाल भी लीड रोल में नजर आए हैं। यह फिल्म 20 को देशभर में रिलीज हुई है और अब फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर नया अपडेट सामने आया है। रोमांस व एक्शन से लबालब 'युध्रा' में सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन की केमिस्ट्री शुरू से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, फिल्म के ट्रेलर और गानों में ही इसकी झलक देखने को मिल गई थी। अब फिल्म रिलीज हो गई है और उसकी रिलीज के बाद भी सबसे ज्यादा मूवी में इसके एक्शन और रोमांस के ही चर्चे हो रहे हैं।

फिल्मों में जाएंगी, तो कोई शादी नहीं करेगा

इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू से बॉलीवुड डेब्यू करने वालीं तृप्ति डिमरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हालांकि, एक समय ऐसा भी था, जब उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आएं। उन्हें सोसाइटी और रिश्तेदारों के खूब ताने सुनने मिलते थे। तृप्ति ने ये भी बताया है कि रिश्तेदारों ने उनके पेरेंट्स से कहा था कि अगर तृप्ति फिल्मों में जाएंगी, तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। हाल ही में तृप्ति डिमरी, कटरीना कैफ की ब्यूटी ब्रांड के-ब्यूटी बाय कटरीना की कन्वर्सेशन का हिस्सा बनी थीं। इस दौरान तृप्ति ने अपना स्ट्रगल शेयर किया है। तृप्ति ने कहा है, 'जब मैं मुंबई आई तो मेरे लिए ये बेहद मुश्किल था। मैं रोज घर से निकलकर ऑडिशन देने जाती थी। ऑडिशन के दौरान एक कमरे में 50-60 लोग होते थे। लोग, समाज, रिश्तेदार मेरे पेरेंट्स से बहुत बुरी बातें कहते थे। वो कहते थे आपने अपनी बेटी को इस प्रोफेशन में क्यों भेजा है। वो पूरी तरह बिगड़ जाएगी। वो गलत लोगों के साथ उठेगी-बैठेगी। वो अपने लिए गलत फैसले लेगी। कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। वो अब शादी नहीं करेगी।

राशिफल

मेष

व्यापार की दृष्टि से अच्छा बीतेगा पर जॉब कर रहे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। आपके सहकर्मी भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऑफिस की राजनीति से बचकर रहे अन्यथा यह दांव आप पर ही उल्टा पड़ेगा। महिलाएं इस समय अपना ज्यादातर ध्यान परिवार में लगाएंगी। बच्चों का समय पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा रहेगा।

वृषभ

वृषभ राशि पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर कोई शंका होने पर अपने परिवारवालों के साथ साझा करें। इससे समाधान मिलेगा। आपने अपना पैसा भूमि संबंधी क्षेत्रों में निवेश कर रखा है तो इस महीन लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। लवलाइफ के लिए यह अच्छा समय है। हालांकि विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की लाइफ उदास रहेगी।

मिथुन

आपको इस माह शिक्षा और करियर के अनुसार उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस माह सकारात्मक परिणाम मिलेगा, आपके सहपाठी भी प्रसन्न होंगे। इस माह में आप अपने प्रतिद्वंद्वियों से सतर्क रहे वर्ना ये नुकसान कर सकते हैं। परिवार में आपसी कलह होने की संभावना है, पर धैर्य रख कर मामले सुलझ सकते हैं। आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के मंदिर जाये और उनसे क्षमा मांगे।

कर्क

इस माह पारिवार में थोड़ा कलह हो सकता हैं व परिवार में किसी बात पर अनबन हो सकती हैं। बच्चों के भविष्य से संबंधित कठोर निर्णय ले सकते है जिसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। रिश्तेदारों में किसी का स्वास्थ्य गंभीर रह सकता है और उनके जीवन पर भी संकट के बादल मंडराएंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं।

सिंह

इस माह आपको अपने प्रेम जीवन में ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता हैं। अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मन-मुटाव हो सकता हैं, इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। किसी के साथ अच्छी बातचीत चल रही है तो उनके साथ बात करते समय सावधानी बरते क्योंकि आपकी अनजाने में कही गयी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है।

कन्या

आपके लिए यह माह शुभ संकेत लेकर आया हैं। पारिवारिक मेलझोल और बढ़ेगा व पुराने मित्रों से भी भेंट हो सकती हैं। दोस्तों के साथ कही घूमने जाने का भी प्लान कर सकते है। खर्चों में भी बढ़ोत्तरी होगी जिस कारण तनाव होगा। माह के आखिरी सप्ताह में लाभ मिलने की भी संभावना हैं। जीवनसाथी संग संबंध और ज्यादा मजबूत होगा व आपसी समझ बढ़ेगी। बच्चों के लिए आप चिंता में रहेंगे।

तुला

तुला राशि के जातकों को लक्ष्मी नारायण राजयोग के शुभ प्रभाव से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। इस दौरान आपके रिश्तों में सुधार आएगा। भाई-बहन के बीच प्रेम बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। इस दौरान धन कमाने के नए साधन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जो खेल प्रतियोगिता से जुड़े हैं उनको भी इस वक्त कामयाबी हासिल होगी।

वृश्चिक

यह माह व्यापारिक दृष्टि से अनुकूल होगा व रुके हुए कार्य बन सकते हैं। किसी काम में कुछ अड़चन आ रही थी या बार-बार प्रयास करने पर भी नही हो पा रहा था तो वह इस माह आसानी से हो जाएगा। घर में किसी सदस्य की शादी की बात भी शुरू हो सकती हैं। अपनी माता के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखे व उन्हें किसी प्रकार का मानसिक कष्ट देने दे बचे। जीवनसाथी संग थोड़े मन-मुटाव वाले हो सकते हैं।

धनु

धनु राशि वालों को पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। उनके साथ मिलकर आप कोई नया बिजनस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही धन से जुड़ी कई पुरानी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। आप काफी समय से जो कर्ज भर रहे थे वह इस समय पूरा हो जाएगा। बुध गोचर के प्रभाव से आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और आपको समृद्धि हासिल होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है।

मकर

मकर राशी वालों को परिवार में भाई-बहनों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। इस बीच आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। व्यापार में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इस बीच आप किसी जमीन का सौदा भी सकते हैं। सामाजिक कार्यों में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सफलतर मिलेगी।

कुंभ

व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। माता-पिता से आर्थिक लाभ हो सकता है। परिवार के सदस्यों से कोई शुभ समाचार मिलेगा। बिजनस में आपको अचानक से लाभ मिलेगा। गोचर की अवधि में मित्रों से आर्थिक लाभ हो सकता है। करियर में आपको आर्थिक लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

मीन

इस माह मंगल थोड़ा भारी हैं। आप किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचे व अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखे। माह के तीसरे सप्ताह में पेट या गले से संबंधित समस्या परेशान करेगी। डायबिटीज के रोगी बाहर का खाना खाने से परहेज रखे। परिवार में कोई नयी खुशी आने का संकेत हैं जिस कारण घर में उल्लास का माहौल रहेगा। जॉब कर रहे लोगों को इस माह थोड़ा कम काम होगा तथा वे अपना समय अन्य कार्यों में दे पाएंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजधानी रांची पहुंचने पर बिरसा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया।

मधुमक्खी व पशुपालन से छोटे किसानों को लाभ मिलेगाः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाकृअनुप -राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा कि किसान आज भी गरीबी में जी रहे हैं. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मधुमक्खी और पशुपालन पर भी जोर दिया और बोला कि इससे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा. इस दौरान मंच पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन,केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ , कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडेय भी मौजूद रहे. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पौधरोपण किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे के साथ किया. उन्होंने कहा कि झारखंड से उनका विशेष लगाव है. 2017 में इस संस्थान के साथ मिलकर कृषि मेले का उद्घाटन किया था. संस्थान ने लाख, रेजिन जैसे कई उत्पादों में विशेष योगदान दिया. लाख के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करने का मौका मिला. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राज्यपाल के दिनों को याद करते हुए बोला कि जब मैं पलामू गई थी तो वहां मुझे बताया गया कि पलाश ,लाख एवं महुवा के नाम पर पलामू का काम रखा गया है. लाख का 55 प्रतिशत उत्पादन होता है जो जनजातीय समुदाय के द्वारा जाता है. लाख आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाता है. जीवन यापन को सुधारने में लाभकारी है. किसानों एवं उद्यमियों के समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है.

राष्ट्रपति ने कहा कि जो सब्जी उत्पादन करते हैं लेकिन उसके बाद सब्जी खराब हो जाती है. इस लिए अधिकारियों से निवेदन है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए.

'मूर्ति गार्डेन' का उद्घाटन

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परिकल्पित झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं से सुसज्जित 'मूर्ति गार्डेन' का उद्घाटन राजभवन में राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में किया गया। इस 'मूर्ति गार्डेन' में युगपुरुष स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गया मुंडा, जतरा टाना भगत, तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर, सिदो-कान्हू, तिलका मांझी, दिवा-किसुन, वीर बुधू भगत के अतिरिक्त परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।

आज का दौर विश्व रुपी का है परंतु दुष्परिणाम से बचना है. अभी भी कई क्षेत्र है जहां हम आगे जा सकते हैं.

राष्ट्रपति ने कहा कि सप्लाई चेन, बाजार की व्यवस्था करने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है. कृषि के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं. सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण की व्यवस्था की है. पीएम किसान निधि से लाभ दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि किसान आज भी गरीबी में जी रहे हैं. उन्होंने मधुमक्खी, पशुपालन से विकास, गांवों में छोटे उद्योगों से किसानों को लाभ होगा. कई वेस्ट चीजें फेंक देते हैं जिससे भी हम प्रसंस्करण कर लाभ ले सकते हैं. देश के साथ विदेशों में भी कृषि उत्पादन में पैठ होनी चाहिए. संस्थान को अन्य संस्थानों से मिलकर काम करना चाहिए.

Medha
Milk
Taazgi Jharkhand Ki
झारखण्ड के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों
से
शहरी उपभोक्ताओं तक
www.fb.com/medhacoop
jmf.coop
7544003456
jmf_coop
medha dairy
www.linkedin.com/in/jharkhand-milk federation-349ab62aa
Medha–Taazgi Jharkhand Ki